वार्षिक विशेषांक

मई, 2025

₹15

www.mediamanch.in

मीडिया मंच

सम्पूर्ण समाचार पत्रिका

पाक पर प्रहार

आतंकियों का काल : आपरेशन सिंदूर

उत्कर्ष के

8 वर्ष

सबका साथ
सबका विकास

- 8 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय ₹46 हजार से बढ़कर ₹1 लाख 24 हजार
- पहली कैबिनेट का पहला निर्णय: ₹36,359 करोड़ से 94 लाख किसानों का ऋण मोचन
- पीएम किसान सम्मान निधि से 2.86 करोड़ किसानों को ₹80 हजार करोड़
- GIS में ₹45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, ₹15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतरे
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.86 करोड़ नि:शुल्क गैस कनेक्शन में यूपी प्रथम
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 22.11 लाख बालिकाएं लाभान्वित
- 6 एक्सप्रेसवे संचालित 11 पर काम जारी, 21 एयरपोर्ट
- 2016 में 21 करोड़ की तुलना में 2024 में 66 करोड़ पर्यटक यूपी आए
- महाकुम्भ 2025 से अर्थव्यवस्था में ₹3.50 लाख करोड़ की अनुमानित वृद्धि
- 8 वर्षों में 204 करोड़ पौधरोपण, 2 लाख एकड़ में हरीतिमा बढ़ी

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

मीडिया मंच

वर्ष - 28

अंक : 01

संपादक
तेज बहादुर सिंह

कार्यकारी संपादक
वीरेन्द्र शुक्ल

समाचार संपादक
वीरेन्द्र सिंह

विशेष संवाददाता
आयुष सिंह

फोटो जर्नलिस्ट
योगेश योगी

मार्केटिंग
सिग्मा ट्रेड विंग्स

लेआउट
विष्णु बिसेन

स्वात्वाधिकारी
'मीडिया मंच पब्लिकेशन्स'
के लिए प्रकाशक, मुद्रक,
सम्पादक टी.बी. सिंह
द्वारा प्रिंट आर्ट,
कैन्ट रोड, लखनऊ
से मुद्रित तथा जी-7,
खुशनुमा कॉम्पलेक्स,
7-मीराबाई मार्ग,
लखनऊ से प्रकाशित
RNI No. : UPHIN/1998/5628

समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र
लखनऊ होगा

वेबसाइट :
www.mediamanch.in

ई-मेल :
mediamanch@ymail.com
tejsingh007@yahoo.com

मोबाइल-09415000151

मैं काशी 26

स्थायी स्तम्भ

अतिथि	11
वास्तु/ज्योतिष	20
ब्यूरोक्रेसी	31
स्वास्थ्य	41
खेल	42
आंखिन देखी	44
सिनेमा	47
यूपीनामा	48

टी.बी. सिंह

संपादकीय

अहम पड़ाव

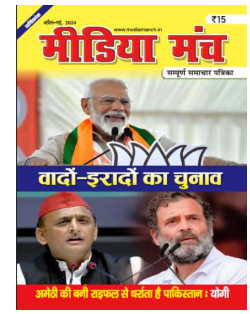

आज जबकि पत्रिका के नाम पर बाजारों में सन्नाटा है। ढूंढने पर शायद ही पत्रिकाओं के दीदार हों। ऐसे में यदि कोई मासिक पत्रिका 27 सालों से प्रकाशन की दुनिया में अपना झंडा बुलंद किए हुए हो तो उस यात्रा को यदि अकल्पनीय यात्रा का दर्जा दिया जाए तो यह बेमानी नहीं होगा। बल्कि पत्रिका के हित में उसके प्रति सार्थक बात होगी। इस पड़ाव तक पहुंचना भले ही अहम है लेकिन इस दौरान जो-जो मुश्किलें, झंझावात और परेशानियों से रुबरु होते हुए निर्बाध गति से प्रकाशन की यह यात्रा चलती रही है। तो यह मीडिया मंच टीम के जोश, जज्बे और जुनून का ही नतीजा है। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता उसी तरह मीडिया मंच का शानदार और जानदार प्रकाशन भी किसी एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित न होकर यह शानदार टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है। 27 साल की यह लंबी और बड़ी यात्रा किसी भी व्यक्ति, संगठन, संस्था अथवा पत्र-पत्रिका के जीवन में बहुत अहम पड़ाव होता है। यह अवसर जहां एक तरफ गर्व और संतोष से भर देने वाला होता है तो वहीं दूसरी तरफ यह अवसर अपनी बीती यात्रा का समीक्षा या विश्लेषण करने का भी होता है। अपने अतीत से सीखने का भी और उसके आधार पर अपने भविष्य के नए लक्ष्य निर्धारित करने का भी स्वर्णिम अवसर होता है। आज मीडिया मंच के लिए यही अवसर है।

अतीत की ओर लौटने पर पुराने दिन, पुराने महीने और पुराने साल के साथ ही संघर्ष की सतत् यात्रा अनायास जेहन में चलचित्र की भांति उभर आती है। वह वर्ष 1998 का था जब मैंने खुद पत्रिका की जगह अपनी पत्रिका निकालने का निश्चय किया था और उस गर्मियों में ही मासिक पत्रिका मीडिया मंच का शुभारंभ कर दिया था। एक तरफ जोश हाई था तो दूसरी तरफ परेशानियां भी टॉप पर थीं। शुरुआती दौर में जो-जो मुसीबतें आईं वह इस कदर परेशान, हैरान और बेचैन कर देने वाली थीं कि लगता था कि प्रकाशन का यह दुष्कर कार्य बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकेगा। लेकिन जब स्टालों पर उस दौर में ढेर सारी पत्रिकाओं के बीच अपनी मीडिया मंच को देखता था तो न केवल शुकून ही मिलता था बल्कि फिर से उत्साहित हो जाता। मन में सवालों के बीच आश्वस्त का यह भाव जग जाता था कि जब तमाम पत्र-पत्रिकाएं निकल सकती हैं और निकल भी रही हैं तो मीडिया मंच क्यों नहीं ?

संघर्ष की यात्रा के बीच संभावनाओं के द्वार भी खुलते गए। कटु-मधु अनुभवों ने कभी निराश किया तो कभी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। कई अनुभवों से गुजरने के दौरान कई सहयोगी बने भी, बिछड़े भी और कई ने मजधार में भी छोड़ने का काम किया। इस लंबी यात्रा में पुराने साथी और सहयोगी एक तरफ यदि किनारे हुए तो दूसरी तरफ नए साथियों, सहयोगियों और शुभचिंतकों ने साथ आकर प्रकाशन यात्रा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बात अगर संपादकीय पक्ष की कि जाए तो जिन वरिष्ठ पत्रकारों ने लंबे कार्यकाल के दौरान अपने लेखन, संयोजन और दूरदृष्टि से इस पत्रिका के अनवरत व सुचारु प्रकाशन में अपना योगदान दिया उसमें तड़ित दा के बाद हनुमान सिंह 'सुधाकर', रवीन्द्र सिंह और अब वीरेन्द्र शुक्ल शामिल हैं। इनमें से हनुमान सिंह 'सुधाकर' का पिछले महीनों में हमसे बिछड़ जाना यानी स्वर्गवासी हो जाना मीडिया मंच के लिए और खुद मेरे लिए बहुत बड़ा झटका रहा है। क्योंकि 80 पार कर लेने के बाद भी गोंडा में रहते हुए अस्वस्थता के बावजूद बहुमूल्य सुझाव और सलाह देकर अब भी पत्रिका से गहरे रूप में जुड़े हुए थे। लेखनी से पत्रकारों ने जहां मीडिया मंच को गतिवान बनाए रखा तो वहीं मैं विशेष रूप से पीसीएस संवर्ग का भी हृदय से अत्यंत आभारी हूं। क्योंकि इस संवर्ग ने समय-समय पर और खासकर मुश्किल के वक्त सहयोग और समर्थन देकर पत्रिका के निरंतरता को बनाए रखने में बहुत बड़ा कार्य किया। जाते-जाते अंत में यही कहना चाहूंगा कि इरादे नेक हों, लक्ष्य साफ और बड़ा हो तो मुश्किलों और परेशानियों को पीछे छोड़ा जा सकता है। मुश्किलों में भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने अंदर का जोश जिंदा रखा। उसी का नतीजा है कि अब भी बड़ी शान और सम्मान के साथ मीडिया मंच लोगों के सामने है। ❑

नवनीत कुमार सहगल
आईएएस (से.नि.)
अध्यक्ष

Navneet Kumar Sehgal
IAS (Retd.)
Chairman

प्रसार भारती | PRASAR BHARATI

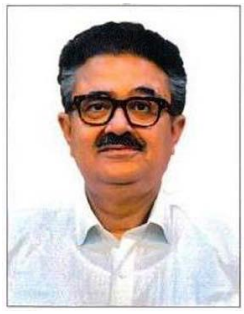

बैशाख 25, शक संवत् 1947
गुरूवार, 15 मई, 2025

शुभकामना संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि देश के प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ इन प्रदेशों की समग्र समस्याओं का शाब्दिक चित्रांकन करने वाली संपूर्ण समाचार पत्रिका **'मीडिया मंच'** सत्ताईस वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका का निर्वहन कर रहा है। यह भी अपार प्रसन्नता का विषय है कि मई 2025 में अपनी स्थापना के 28वें वर्ष में प्रवेश करने पर संपादक मंडल द्वारा विशेषांक का प्रकाशन कर अपने सुधी-पाठकों को उपहार देने जा रही है।

मुझे अटूट विश्वास है कि विगत वर्षों में पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुसरणीय कीर्तिमान स्थापित करने वाली यह पत्रिका भविष्य में भी अपने दूरदर्शी विचारों और सारगर्भित विषयवस्तु के माध्यम से मरे भरोसे पर खरी उतरेगी।

'मीडिया मंच' पत्रिका के इस विशेषांक के प्रकाशन के लिए संपादक मंडल और सभी सम्माननीय पाठकों को मेरी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई।

(नवनीत कुमार सहगल)

सेवा में,
श्री तेज बहादुर सिंह
संपादक, मीडिया मंच
जी-7, खुशनुमा कॉम्पलेक्स, 7 मीराबाई मार्ग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 206001

आलोक सिंह

आईएएस
जिला मजिस्ट्रेट
एवं कलेक्टर

जिलाधिकारी
कानपुर देहात

संदेश

ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि मीडिया मंच पत्रिका अपने सजग संपादकीय नेतृत्व में 27 वर्षों की प्रकाशन यात्रा पूरी कर मई 2025 में 28वें वर्ष में प्रवेश करेगी। समाचारों एवं विचारशील लेखों से संपन्न इसके हर अंक की सामग्री पाठकों के लिए चिंतन मनन एवं ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत सिद्ध होती रही है। इसके अनेक अंकों में खोजी पत्रकारिता की बानगी भी देखने को मिली है।

इस अवसर पर आपके द्वारा प्रकाशित किए जा रहे विशेषांक की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(आलोक सिंह)

आर.पी. सिंह

आईएएस (Retd.)
सदस्य

उच्च शिक्षा आयोग
उ.प्र.

संदेश

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि 'मीडिया मंच' मासिक पत्रिका का प्रकाशन विगत 27 वर्षों से अनवरत होता आ रहा है। मीडिया मंच मई, 2025 में पत्रिका के प्रकाशन के 27 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 'वार्षिक विशेषांक' प्रकाशित करने जा रहा है। आशा करता हूं कि इस प्रकाशित होने वाली पत्रिका में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नागरिकों, बुद्धजीवियों व जन-सामान्य के पठन-पाठन हेतु शासन की उपलब्धियां, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के साथ समग्र समस्याओं का शब्दिक चित्रांकन किया जाएगा जो पत्रिका के पाठकों के साथ-साथ जन-सामान्य के लिए भी उपयोगी होगी।

अतः उपर्युक्त सूक्ष्म शब्दों के साथ मैं वार्षिकांक विशेष के अवसर पर इस पत्रिका 'मीडिया मंच' के सफल प्रकाशन हेतु आप तथा इससे जुड़े सभी सम्बन्धित को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

भवदीय,
(आर0 पी0 सिंह)

आंजनेय कुमार सिंह

आईएएस

आयुक्त
मुरादाबाद मंडल

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि ''मीडिया मंच'' मासिक पत्रिका अपने 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड की समग्र समस्याओं को शाब्दिक चित्रांकन के साथ प्रकाशित किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के आम नागरिक लाभान्वित होंगे तथा दोनों राज्यों की समस्यायें सामने आने पर उनका निराकरण करते हुए राज्य के विकास में पत्रिका के प्रकाशन से सहयोग मिलेगा।

मैं इस शुभ अवसर पर पत्रिका के सम्पादक एवं उनके सहयोगी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)

समीर

आईएएस
विशेष सचिव

वित्त विभाग
उ.प्र. शासन

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुयी है कि प्रदेश की प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका मीडिया मंच का 27वां विशेषांक प्रकाशित होने जा रहा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि पत्रिका ने अपनी स्थापना के 27 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। मीडिया मंच प्रत्येक माह अपने पाठकों के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुयी तथ्यपरक व जन सरोकार की खबरों को प्रकाशित करता है तथा शासन की नीतियों आदि के संबंध में भी आलोचनात्मक व समीक्षात्मक टिप्पणियां प्रकाशित करता है। पत्रिका का नियमित पाठक होने के नाते रजत जयंती विशेषांक के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

मैं पत्रिका की संपादकीय टीम को विशेष रूप से शुभकामनाएं देना चाहूंगा तथा पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास व प्रसार के लिए भी मैं अपनी शुभेच्छायें प्रकट करता हूं।

(समीर)

कामता प्रसाद सिंह
आईएएस

अपर आयुक्त
खाद्य एवं रसद
विभाग

संदेश

यह अत्यंत हर्ष की बात है कि 'मीडिया मंच' मासिक पत्रिका विगत 27 वर्षों से नियमित प्रकाशन के बाद अब मई 2025 में 28वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई।

लोकतंत्र में चौथे खम्भे यानी समाचार पत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाचार जनता और सरकार की उपलब्धियों एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का विशेष योगदान होता है। इस दृष्टि से मीडिया मंच पत्रकारिता के मापदंडों पर खरी उतर रही है। इस अवसर पर प्रकाशित होने वाले वार्षिक विशेषांक में ऐसी रचनात्मक सामग्री का समावेश किया जाएगा जो कि पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी सिद्ध होगा ऐसा मेरा विश्वास है।

कामता प्रसाद सिंह

शिशिर
आईएएस
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
8 तिलक मार्ग लखनऊ

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि ''मीडिया मंच'' मासिक पत्रिका अपने 27 वर्षों की प्रकाशन यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण कर मई, 2025 में 28वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। लगातार इतने वर्षों तक इसकी गुणवत्ता, यथार्थपरकता व निष्पक्षता को बरकरार रखते हुए आपने इस पत्रिका का जो स्थान पत्रकारिता जगत में बनाया है, वह अत्यधिक सराहनीय है और इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को साधूवाद देता हूँ।

मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप इस पत्रिका के माध्यम से स्वस्थ पत्रिका की मुहिम को जारी रखेंगे।

(शिशिर)
आई0ए0एस0
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

इन्द्र विक्रम सिंह
आईएएस
आयुक्त एवं निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद
उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खंड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदेश

हर्ष का विषय है कि मीडिया मंच पत्रिका लगातार अपने प्रकाशन के 27वां वर्ष पूर्ण कर मई 2025 में 28वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। राजनीति से लेकर समाज के संवेदनशील पहलुओं का पैनी दृष्टि से रेखांकन इस पत्रिका की विशेषता है।

इस अवसर पर प्रकाशित होने वाले विशेषांक के लिए पत्रिका के संपादकीय टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(इन्द्र विक्रम सिंह)

एन.के. सिंह चौहान
विशेष कार्याधिकारी

मा. मुख्यमंत्री
उ0प्र0 सरकार

संदेश

27 वर्ष पूरे हो गए हैं, 28वें वर्ष में मीडिया मंच प्रवेश करने जा रही है। सफलतम 27 वर्षों का इतिहास पाठकों के स्मृति पटल पर है।

इस पत्रिका के उद्भव से शैशवावस्था तक मैं इसका साक्षी रहा हूं। मैं आशान्वित हूं कि यह पत्रिका अपने सफलतम अगणित वर्षों तक जीवित रहेगी और पाठकों के लिए न केवल शासकीय योजनाओं की सूचना देती रहेगी अपितु जनोपयोगी व समसामयिक विषयों पर सारगर्भित लेख के साथ अन्य विषयों वास्तु / ज्योतिष, खेल जैसे स्थायी स्तम्भों के माध्यम से पाठकों के लिए रूचिपूर्ण सूचनाएं प्रस्तुत करती रहेगी।

मैं, श्री तेज बहादुर सिंह, संपादक व उनके संपादन मण्डल द्वारा की गयी समाज के प्रति सेवा का आभार व्यक्त करते हुए आशा करता हूं कि पत्रिका अपने सफलता के नए आयाम की ओर इसी तरह निरन्तर प्रगति करेगी।

मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

19.04.2025
(एन0 के0 एस0 चौहान)
विशेष कार्याधिकारी
मा0 मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन

मनोज कुमार
आईएएस
सचिव

उच्च शिक्षा आयोग
उ.प्र.

संदेश

मुझे यह जानकर अतीव हर्ष हो रहा है कि मासिक पत्रिका ''मीडिया मंच'' अपने प्रकाशन के 27 वर्ष पूर्ण कर रही है। विगत 27 वर्षों से इस पत्रिका के नियमित पाठक के रूप में मैने यह अनुभव किया है कि पत्रिका की विषय-वस्तु अत्यंत सम-सामयिक एवं ज्वलंत विषयों को विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत करने वाली होती है। प्रशासनिक वर्ग, विशेषतः राज्य सिविल सेवा की समस्याओं एवं मुद्दों को अनेक अंकों में मुखरित स्वर प्रदान किया गया है साथ ही संवर्ग के अधिकारीगण के अभिनव प्रयोगों एवं उपलब्धियों को सम्यक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

अपनी भविष्यगामी प्रकाशन-यात्रा में ''मीडिया मंच'' पत्रकारिता के उच्चस्तरीय मानदंड़ों पर खरा उतरकर निर्भीक, निष्पक्ष एवं दिग्दर्शक की भूमिका का निर्वहन करें हृदयतल से ऐसी कामना करता हूं।

शुभकामनाओं सहित,

भविष्ठ
मनोज कुमार

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
आईएएस
विशेष सचिव

पशुधन विभाग
उ.प्र. शासन

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि ''मीडिया मंच'' अपने प्रकाशन के 27 वर्ष पूरा कर 28वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस अवसर पर पत्रिका के वार्षिकांक भी प्रकाशित किया जा रहा है। आज के परिवेश में सामाजिक एवं समसामयिक विषयों को स्पष्ट सोच के साथ विचारोत्तेजक रूप में मुखरित करना मीडिया मंच का दायित्व है। ऐसे में उपरोक्त सरोकरों का स्पष्ट रूप से सम्पादन करने का साहस एवं सार्थक प्रयास हेतु ''मीडिया मंच'' को साधुवाद एवं हार्दिक शुभेच्छा।

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय

संजय चौहान
आईएएस

जिलाधिकारी
अमेठी

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मीडिया मंच मासिक पत्रिका 27 वर्षों की अनवरत प्रकाशन यात्रा पूरी कर मई 2025 में 28वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। आप की पत्रिका रचनात्मक कार्यों व सारगर्भित लेखों से परिपूर्ण होती है तथा विभिन्न जानकारियां जानमानस तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है।

मैं मीडिया मंच पत्रिका के 27 वर्षों के सफल प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

30.4.25
(संजय चौहान)
जिलाधिकारी,
अमठी।

पुष्पराज सिंह
पीसीएस

अध्यक्ष
उ.प्र. पीसीएस
एसोसिएशन

संदेश

बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि मीडिया मंच ने अपने प्रकाशन के 27 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मैं मीडिया मंच का नियमित पाठक रहा हूं इसमें राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक विषयों से संबंधित जो लेख प्रकाशित किए जाते है वे विचारोत्तेजक एवं सर्वांगीण जानकारी देने वाले होते हैं।

पत्रिका का प्रत्येक अंक बीते हुए महीने की जीती-जागती तस्वीर बनकर सामने आती है। मेरी कामना है कि आगे भी मीडिया मंच इसी प्रकार से चेतना का एक सबल स्रोत बनकर हम सभी के सामने आती रहे।

पुष्पराज सिंह

अखिलेश सिंह
आईएएस

आयुक्त
बस्ती मण्डल
बस्ती

संदेश

यह अत्यन्त हर्ष और गर्व का विषय है कि मीडिया मंच पत्रिका ने प्रकाशन के शानदार 27 वर्ष पूरे कर लिए। इस दौरान पत्रिका ने समय-समय पर जो लेख और सारगर्भित टिप्पणियां प्रकाशित की हैं उससे आमजन को अत्यधिक ज्ञान का लाभ प्राप्त हुआ है।

मेरा विश्वास है कि पत्रिका भविष्य में इसी तरह नियमित प्रकाशन से आमजन को शिक्षित और जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएगी। पत्रिका की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मीडिया मंच परिवार को शानदार और सुन्दर ढंग से सफल प्रकाशन पर बधाई प्रेषित करता हूं।

अखिलेश सिंह

डॉ. अरूणवीर सिंह
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक
विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

संदेश

मुझे जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि ''मीडिया मंच'' मासिक पत्रिका मई, 2025 में 27 वर्षों का सफर सफलता पूर्वक पूरा कर 28 वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। आपकी पत्रिका निरन्तर इतने वर्षों की गुणवत्ता और निष्पक्षता को बरकरार रखते हुए पाठकों के लिए शासकीय योजनाओं की सूचना उपलब्ध कराने के साथ-साथ जनोपयोगी व समसामयिक विषयों पर लेखों व पाठकों के लिए रूचिपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती रही हैं। मैं यह आशा करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार आपकी पत्रिका अपने पाठकों को महत्वपूर्ण जानकारी और सूचनाएं उपलब्ध कराती रहेगी।

मैं श्री तेज बहादुर सिंह, संपादक, मीडिया मंच व उनके सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

भवदीय

30/4/25

(डॉ0 अरूणवीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

डॉ. अखिलेश मिश्रा
आईएएस

अपर निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन
आयोग उ0प्र0

संदेश

आदरणीय सिंह साहब,

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि, मासिक पत्रिका ''मीडिया मंच'' इस वर्ष अपनी 27वीं वर्षगांठ मना रहा है।

समाज एवं राष्ट्र के विकास में पत्र एवं पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मीडिया मंच द्वारा इस कार्य में अपना विशेष योगदान दिया है। आशा है कि, वर्षगांठ विशेषांक के द्वारा जन-सामान्य को भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी।

मीडिया मंच के 27वें वर्षगांठ विशेषांक के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

सादर

डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा

पंकज सिंह
पीसीएस

सचिव
नेडा

संदेश

मुझे प्रसन्नता है कि मीडिया मंच मासिक पत्रिका मई 2025 में अपने प्रकाशन के 28वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। निष्पक्ष पत्रकारिता एवं विचारोत्तेजक रिपोर्टिंग के कारण उसके हर अंक की प्रतीक्षा रहती है, आपकी संपादकीय टीम ने उसे वैचारिक ऊँचाइयां देने का प्रयास किया है। पत्रिका के कुछ लेख विषय वस्तु और रोचकता के कारण प्रायः चर्चा का विषय होते हैं।

पत्रिका की 27 वर्षों की सफल और सार्थक प्रकाशन यात्रा के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(पंकज सिंह)
सचिव,नेडा

देवेन्द्र सिंह कुशवाहा

आईएएस
विशेष सचिव

आबकारी विभाग
उ.प्र. शासन

संदेश

यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि मीडिया मंच पत्रिका अपने प्रकाशन के 27 वर्ष पूरा कर चुकी है। इतने वर्षों से मीडिया मंच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नौकरशाही पर विश्लेषणात्मक समाचारों एवं लेखों का प्रकाशन करते हुए जनता एवं व्यवस्था के बीच प्रभावी सेतु का कार्य करता रहा है। इसके लिए मीडिया मंच के सम्पादकीय टीम को मेरी बधाई एवं शुभकामनाएं।

भवनिष्ठ

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)

चन्द्र भूषण सिंह

आईएएस

सचिव
माध्यमिक शिक्षा विभाग
उ.प्र. शासन

संदेश

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि मीडिया मंच माह मई, 2025 में पत्रिका के प्रकाशन के 27 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ''वार्षिकांक'' प्रकाशित करने जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकाशित होने वाली पत्रिका में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नागरिकों, बुद्धजीवियों व जन-सामान्य के पठन-पाठन हेतु शासन की उपलब्धियां, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के साथ समग्र समस्याओं का शाब्दिक चित्रांकन किया जाएगा जो पत्रिका के पाठकों के साथ-साथ जन-सामान्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी होगा।

अतः उक्त शब्दों के साथ मैं वार्षिकांक विशेषांक के अवसर पर ''मीडिया मंच'' के सफल प्रकाशन हेतु आप तथा इससे जुड़े सभी संबंधित को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

भवदीय,

(चन्द्रभूषण सिंह)

उमेश प्रताप सिंह

आईएएस
संयोजक / महासचिव

उ.प्र. प्रोन्नत
आईएएस मंच

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मासिक समाचार पत्रिका 'मीडिया मंच' अनवरत प्रकाशन यात्रा तय करते हुए माह मई-2025 में '27वें वर्षगांठ' के अवसर पर 'वार्षिकांक विशेषांक' प्रकाशित कर रहा है। इस समाचार-पत्रिका के माध्यम से वर्तमान में घटित होने वाली सामाजिक, आर्थिक-राजनैतिक एवं जनहितार्थ आदि विषयों से जुड़ी विविध घटनाओं की सटीक जानकारी प्राप्त होती रहती है।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि समाचार-पत्रिका 'मीडिया मंच' जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए चतुर्थ स्तम्भ के रूप में पत्रकारिता को संबल प्रदान करेगी।

वार्षिकांक के इस शुभ अवसर पर 'मीडिया मंच' परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

उमेश प्रताप सिंह

अरूण प्रकाश

आईएएस
विशेष सचिव

नगर विकास विभाग
उ.प्र. शासन

संदेश

बड़ी प्रसन्नता के विषय है कि ''मीडिया मंच'' सम्पूर्ण समाचार पत्रिका अपने 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर वार्षिकांक का प्रकाशन करेगी।

पत्रिका में प्रकाशित होने वाली सामग्री बहुत की सारगर्भित एवं जनमानस के लिए उपयोगी होती है। वर्षों से पत्रिका का विषय वस्तु सम सामयिक एवं ज्वलंत मुद्दों को विश्लेषणात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता रहा है।

पत्रिका की संपादकीय टीम को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

(अरूण प्रकाश)
आई0ए0एस0

डॉ. दिनेश चन्द्र
आईएएस

जिलाधिकारी
जौनपुर

संदेश

यह जानकर प्रसन्नता है कि मीडिया मंच पत्रिका अपने प्रकाशन के 27 वर्ष पूर्ण कर मई 2025 में 28वें वर्ष में प्रवेश करेगी। लगातार इतने सालों तक इसकी गुणवत्ता, यथार्थपरकता व निष्पक्षता को बरकरार रखते हुए या कह लें कि उसमें निरंतर अभिवृद्धि करते हुए आपने इस पत्रिका का जो स्थान पत्रकारिता जगत में बनाया है, यह अत्यधिक सराहनीय है और इसके लिए मैं आपको तथा आपकी टीम को साधुवाद देता हूं। सुदीर्घ वर्षों तक पत्रकारिता के माध्यम से समाज, प्रदेश एवं राष्ट्र की सेवा में मीडिया मंच पत्रिका में प्रकाशित लेख से जनसमुदाय लाभान्वित हुआ। महाकुम्भ विषयक महाकुंभ-2025 के संबंध में मीडिया मंच में प्रकाशित लेख-आलेख अत्यंत प्रभावशाली एवं सनातन धर्म के विषय में प्रकाशित तथ्य मर्मस्पर्शी एवं प्रभावशाली रहे, जिससे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा है।

अतः आपकी राजनीतिक, सामाजिक व प्रशासनिक क्षेत्र की रिपोर्ट व समीक्षाएं जानकारी व प्रज्ञा से भरपूर होती हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप इसी तरह पत्रिका के माध्यम से स्वस्थ पत्रकारिता की मुहिम को जारी रखेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

भवनिष्ठ
Dmd
(डा० दिनेश चन्द्र)
05/05/2025

संतोष बहादुर सिंह
पीसीएस
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

जिलाधिकारी कार्यालय
सहारनपुर

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि ''मीडिया मंच'' समाचार पत्रिका विगत कई वर्षों से प्रदेश संबंधी सम-सामयिक घटनाओं, प्रशासनिक संवर्ग के उच्च आदर्शों, खेल इत्यादि के प्रोत्साहन हेतु अपने प्रकाशन के माध्यम से सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मीडिया मंच में जीवन के विविधि पहलुओं एवं राष्ट्रहित के सामयिक प्रकरणों के साथ-साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय योजनाओं, कार्यक्रमों, उत्सवों आदि तथ्यों का सुस्पष्ट एवं सचित्र प्रस्तुतीकरण एक प्रशंसनीय एवं सराहनीय प्रयास है।

मुझे आशा है कि मीडिया मंच के माध्यम से उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमताओं के उद्धरणों, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की सम्यक जानकारी के साथ उसके विविध पहलुओं के विस्तृत विवरण, राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, खेलकूद इत्यादि के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आप जनमानस के सर्वांगीण विकास में यह पत्रिका लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में सहायक सिद्ध होगी।

मैं मीडिया मंच को प्रचारित एवं प्रसारित सराहनीय तथ्यों के सफल प्रकाशन हेतु शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि मीडिया मंच वर्तमान परिदृश्य में घटित हो रहे सम-सामयिक प्रकरणों, उच्च प्रशासनिक परिलब्धियों, शासकीय योजनाओं, खेलकूद इत्यादि के मार्गदर्शक प्रकाशन के रूप में सफल होगा।

(संतोष बहादुर सिंह)
पीसीएस
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
सहारनपुर

मंगला प्रसाद सिंह
आईएएस

जिलाधिकारी
हरदोई

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि देश के प्रमुख हिन्दी भाषी राज्यों विशेषतः उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के साथ ही इन दो प्रदेशों की समग्र समस्याओं को शाब्दिक चित्रांकन के साथ किसी भी संपूर्ण समाचार पत्रिका की कमी का जो अनुभव किया जा रहा था, उसे ''मीडिया मंच'' मासिक पत्रिका विगत 27 वर्षों से पूरा करती आ रही है। मई 2025 में पत्रिका का ''वार्षिकांक'' विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है।

पत्रिका के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वास है कि उक्त विशेषांक अपने उद्देश्यों में शत्-प्रतिशत सफल होगा।

(मंगला प्रसाद सिंह)
जिलाधिकारी,
हरदोई।

मानवेन्द्र सिंह
आईएएस
महानिदेशक

आयुष विभाग
उ. प्र.

संदेश

सेवा में
तेज बहादुर सिंह
संपादक मीडिया मंच।

महोदय बड़े हर्ष का विषय है कि प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका 'मीडिया मंच' 27 वर्ष पूरा कर रहा है यह आपके कुशल संपादन का ही प्रतिफल है। मीडिया मंच के माध्यम से आपके द्वारा ऐसी निरंतर सूचना आम जन को प्रेषित की जा रही हैं, जिससे इस माध्यम से प्रबुद्धवर्ग सदैव लाभान्वित होता रहा है।

27 वें स्थापना दिवस पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

24/4
(मानवेन्द्र सिंह)
आई0ए0एस0

गिरिजेश कुमार त्यागी
आईएएस

विशेष सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन

संदेश

मुझे यह जानकर असीम प्रसन्नता हो रही है कि ''मीडिया मंच'' मासिक पत्रिका 27 वर्षों की प्रकाशन यात्रा पूरी कर चुकी है। इस अवसर पर प्रकाशित होने वाले वार्षिकांक विशेषांक पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं एवं मीडिया मंच सम्पादकीय टीम को कोटि-कोटि बधाई।

मुझे विश्वास है कि ये पत्रिका अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। उज्जवल भविष्य हेतु मेरी शुभकामनाएं।

भवदीय,
(गिरिजेश कुमार त्यागी)

शीलधर सिंह यादव
आईएएस

विशेष सचिव
विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग
उ0प्र0 शासन

संदेश

विगत 27 वर्षों से 'मीडिया मंच' एवं सम्पूर्ण समाचार पत्रिका के रूप में राजनीतिक, प्रशासनिक एवं अन्य सामाजिक विषयों से संबंधित उ.प्र. की खबरों का प्रकाशन समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अत्यन्त सारगर्भित, निरपेक्ष एवं गरिमापूर्ण ढंग से कर रही है।

मैं पत्रिका के वार्षिकांक विशेषांक पर अन्तः हृदय से शुभकामनायें प्रेषित करते हुए विश्वास करता हूँ कि मीडिया मंच के सम्पादक एवं उनके सहयोगी भविष्य में इसी प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए नई ऊँचाईयों को प्राप्त करेंगे।

शुभकामनाओं सहित।

(शीलधर सिंह यादव)
आई0ए0एस0

निरंतर, निष्काम जनसेवा अपना लक्ष्य बनाएं अधिकारी

जन सुनवाई सर्वोच्च प्राथमिकता : मंगला प्रसाद सिंह

उच्च न्यायालय ने की सराहना

वीरेन्द्र सिंह

गरीब, वृद्ध, विधवा और अन्य दुखी जन की सुनवाई सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी समस्या या शिकायत के समाधान से आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। इसके लिए डीएम हरदोई ने आईजीआरएस की तरह ही जनपद का अलग जन सुनवाई पोर्टल बनाया है। हरदोई प्रदेश का पहला जनपद है, जहां पर डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ किसी भी स्तर पर शिकायत आनलाइन दर्ज कराने पर उसे एक पर्ची दी जाती है। उसपर पंजीकरण नंबर होता है। समस्या का समाधान या शिकायत का निवारण होने तक नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि यदि वही शिकायत तीसरी बार आती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अभी हाल ही में ऐसे ही मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक कानूनगो और लेखपाल को निलंबित किया गया है।

मीडिया मंच से एक मुलाकात में जिलाधिकारी हरदोई मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि वह बैठकों में अपने अधीनस्थों को संदेश देते हैं कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आंख बंद करके गरीब, असहाय लोगों के चेहरे को देखें, विचार करें और उनके हित में कार्य करें। उल्लेखनीय है कि मंगला प्रसाद सिंह पूर्वांचल के आतंक के पर्याय एक भू माफिया, बाहुबली और असामाजिक व्यक्ति के गुरूर और गैर कानूनी कार्यों को जमीदोंज करने में प्रशासनिक दृढ़ता और निर्भीकता का परिचय देते हैं। वहीं दूसरी ओर जब किसी मजलूम और गरीब के मदद की बात आती है तो उनका दिल पसीज जाता है। वह खुलकर उसके साथ खड़े होते हैं और इंसाफ करके ही दम लेते हैं।

वाराणसी (वर्तमान काशी) में तीन वर्षों तक एडीएम सिटी के रूप में अपने कार्यकाल के बारे में वह बताते हैं कि वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरीडोर विकसित हुआ है इसका शुभारंभ उनके कार्यकाल में हो गया था। उसका लेआउट और डिजाईन बन गया था। काशी की तंग गलियों के चौड़ीकरण में उन्होंने दिन-रात कार्य किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के कब्जे को हटवाने के लिए रात 11 बजे से सुबह तक वह डटे रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पास सचिव वाराणसी विकास प्राधिकरण का भी चार्ज था। सचिव के रूप में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा तट तक मार्ग विकसित करने की दिशा में कार्य किया था। उस समय काशी में सड़क चौड़ी न होने की वजह से यातायात का भारी दबाव रहता था। वह स्वयं फील्ड में उतरकर लोगों को ट्रैफिक डायवर्जन के जरिए सुगम आवागमन सुविधा उपलब्ध कराते थे।

सीईओ काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में उन्होनें वीआईपी पास की वजह से मंदिर में होने वाली भीड़ की समस्या का निस्तारण किया। उनके समय में लिया गया निर्णय आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर में बदस्तूर लागू है। सुबह साढ़े तीन बजे होने वाली मंगला आरती

के लिए बनने वाले वीआईपी पास पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था जो आज भी बदस्तूर लागू है। मंगला प्रसाद सिंह का शुरु से जन संवाद के जरिए समस्याओं के समाधान पर विश्वास था। इसलिए किसी जनपद में कानून व्यवस्था की कोई गंभीर समस्या उनके कार्यकाल में नहीं आई। वह पूरी तरह जागरूक रहते थे और नागरिकों से संवाद बनाए रखते थे। काशी में साल के दो महीनों को छोड़कर बाकी 10 महीने किसी न किसी त्योहार या उत्सव का आयोजन होता है। जिला प्रशासन को भारी भीड़ के नियंत्रण और त्योहारों के सकुशल संपन्न होने के लिए फील्ड में उतरकर काफी मशक्कत करनी होती है। उनका विश्वास था कि विध्न पैदा करने वाले तत्वों से दूरी बनाकर रखें और सहयोग करने वाले सामाजिक लोगों से संपर्क बनाकर रखें। यही उनके कुशल प्रशासन का मूलमंत्र है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव के रूप में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में लाया गया कि बहुत से आवंटियों को प्लाट पर कब्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने तत्काल पूरी सूची बनवाई और सबको कब्जा दिलाया। उस समय भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसानों की कई समस्याएं लंबित थीं। उन सभी का निस्तारण कर किसानों को उनका वाजिब हक दिलाया। उन्हीं के समय में दुबग्गा में प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की मूर्ति स्थापित हुई, अवध सेंटर का निर्माण हुआ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में पहली बार ई आक्सन, ई-टेंडर की शुरूआत की गई। प्लास्टिक से सड़कों का निर्माण उन्हीं के समय में शुरु हुआ था।

डीएम गाजीपुर रहते हुए मंगला प्रसाद सिंह को दो साल की अवधि में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पूरा जनपद और आसपास के कई जनपद माफिया, दबंगों और बदमाशों के चंगुल में कराह रहे थे। गरीब, बेबस लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। किसी की भी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा हो जाता था। सड़क पर मां-बहनों का राह में चलना दूभर था। जनपद के लोग दहशत के साए में कराह रहे थे। उन्होंने डीएम के रूप में कार्यभार ग्रहण करते ही बड़ी ही निर्भीकता और प्रशासनिक दृढ़ता के साथ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। माफियाओं के अवैध रूप से बनाए गए होटल, अस्पताल, फार्मेसी, मकान और अन्य प्रतिष्ठानों का नियमानुसार ध्वस्तीकरण किया गया। अवैध ठेकों और पट्टों पर अंकुश लगाकर जनसामान्य

को राहत दिलाई गई। उन्होंने बताया कि गैर कानूनी रूप से फूड कारपोरेशन आफ इंडिया (एफसीआई) के गोदाम पर माफिया के साले को 16 लाख रूपये मिलते थे। इसी तरह से अन्य कारोबार के जरिए अवैध वसूली का सिलसिला चलता था। अवैध वसूली के इस धंधे पर सख्ती के साथ अंकुश लगाया गया।

डीएम गाजीपुर ने एक महिला डॉक्टर का जिक्र करते हुए बताया कि शहर के बीचो-बीच उसकी जमीन थी, जिस पर वह नर्सिंग होम बनाना चाहती थी। उस जमीन को हथियाने की फिराक में बाहुबली के गुंडे उसके घर के पास बैठना शुरु कर दिए। उस महिला डॉक्टर की दो सयानी बेटियां थीं। उसे बेटियों को उठा लेने की धमकी दी जाने लगी, वह डर गई। मजबूर होकर महिला डॉक्टर ने अपनी व्यावसायिक उपयोग की कीमती जमीन को बाहुबली के नाम पर रजिस्ट्री कर दी। इसी तरह के दहशत पैदा करके जमीन हथियाने और सरकारी भूमि पर कब्जा करने के अनेकों उदाहरण हैं। डीएम रहते हुए मंगला प्रसाद सिंह ने सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया और जिन व्यक्तियों की जमीन को अवैध रूप से हड़पा गया था। उन्हें वापस दिलाया। इसके अलावा उन्हीं के कार्यकाल में बनारस-गाजीपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा था। इस निर्माण के लिए भू अधिग्रहण की दिक्कतों को दूर कर एक्सप्रेस वे का मार्ग प्रशस्त किए।

वर्तमान में डीएम हरदोई के रूप में कार्यरत मंगला प्रसाद सिंह पूर्व जनपदों की तरह यहां भी अपनी प्रशासनिक दृढ़ता और मानवीय संवेदनशीलता के साथ ढाई साल से कार्यरत हैं। पहले हरदोई में फोर लेन या सिक्स लेन सड़क नहीं थी। अब लखनऊ-हरदोई की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। हरदोई से गुजरने वाला गंगा एक्सप्रेस वे लगभग बनकर तैयार है। हरदोई मास्टर प्लान को धरातल पर उतारने के लिए वह निरंतर सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि हरदोई जनपद आयुष्मान कार्ड बनाने में पहले पायदान पर है। इसके अलावा अटल चौक के निर्माण सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट में अत्याधुनिक वीडियो कांफ्रेंसिंग हाल का निर्माण कार्य शुरु हो गया है। यह हाल सभी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होगा। राज्य की राजधानी लखनऊ से लेकर जनपद के सुदूर ब्लाक, तहसील कनेक्ट रहेंगे। इससे सूचनाओं का आदान-प्रदान सुगम होगा।

नए लोक सेवकों के बारे में उनका संदेश है कि जिस उद्देश्य से वे सेवा में आए हैं उसे

बरकरार रखें। निरंतर और निष्काम भाव से जनसेवा को अपना लक्ष्य बनाए रखें। उल्लेखनीय है कि उनके कार्यों की सराहना करते हुए यूपीडा ने अपने प्रशस्ति पत्र में कहा कि औद्योगिक गलियारे की स्थापना हेतु चिन्हित भूमि को भू स्वामियों की सहमति के आधार पर तीन माह से कम अवधि में क्रय कराया गया। इतनी कम अवधि में उक्त उपलब्धि आपके कुशल प्रबंधन, अनुश्रवण एवं नेतृत्व तथा जनपदीय टीम की सक्रियता व प्रभावी कार्यशैली के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है।

जिलाधिकारी हरदोई की प्रशंसा करते हुए कमिश्नर लखनऊ ने अपने प्रशस्ति पत्र में उल्लेख किया है कि जिलाधिकारी द्वारा माइन मित्र, तथा खनन विभाग द्वारा विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छ एवं पारदर्शी खनन प्रशासन हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विभाग से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने एवं अवैध खनन / परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली को एक छतरी के नीचे लाते हुए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा विकसित पोर्टल का बेहतर ढंग से प्रयोग किया गया है। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा किए गए नेतृत्व एवं सतत पर्यवेक्षण से ही माइन मित्र एक जन उपयोगी पोर्टल बन गया है। जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान को जनपद में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि जनपद में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी स्तर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उपलब्धि के कारण पूरे देश में उत्तर प्रदेश की प्रगति में भी सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्राप्त प्रशस्ति पत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी हरदोई को वर्ष 2023 में जनपद में मतदाता सूची प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय, उत्कृष्ट एवं अनुभव कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में संसदीय क्षेत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का कार्य सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न तरीके से संपन्न करने के लिए जिलाधिकारी की सराहना की गई। इसी तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा भी जिलाधिकारी हरदोई की प्रशंसा की गई।

जिलाधिकारी हरदोई ने अपने नेतृत्व क्षमता का अदभुत कौशल विकसित किया है। इसके लिए वह रोज सुबह 10 बजे से एक बजे तक अपने कार्यालय में बैठते हैं। इस दौरान तहसील, ब्लाक, नगर पालिका के अधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें रहते हैं। जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, ब्लाक प्रमुख, ईओ के पास जो भी शिकायतें या समस्याएं आती हैं, उनका त्वरित समाधान किया जाता है। इस दौरान डीएम के पास भी जो जन सुनवाई के मामले आते हैं, उनको तत्काल संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इस तंत्र को विकसित करने से शिकायतों के निस्तारण में सहूलियत होती है साथ ही सभी जनपदीय प्रशासनिक अधिकारी समय से अपने कार्यालय में बैठकर जन सुनवाई करते हैं। अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य परस्पर सामंजस्य का भी यह एक नायाब तरीका है।

विलक्षण प्रतिभा, अप्रतिम आत्मविश्वास और सामाजिक सरोकार से संपन्न मंगला प्रसाद सिंह सिविल सेवा परीक्षा की आयु न होने के पहले ही बीएसएफ और सीआरपीएफ में चयनित हो गए थे। जब पीसीएस परीक्षा की अर्हता हुई तब उन्होंने मध्य प्रदेश पीसीएस में सफलता अर्जित की। इसी बीच उत्तर प्रदेश पीसीएस में चयन हो जाने के कारण उन्होंने एमपी पीसीएस को छोड़ दिया।

सुल्तानपुर के रहने वाले मंगला प्रसाद सिंह 2012 बैच के आईएएस हैं। 1999 में पीसीएस अधिकारी के रूप में राजकीय सेवा में आए थे। डिप्टी कलेक्टर जौनपुर, बस्ती, हमीरपुर, मुरादाबाद, सिटी मजिस्ट्रेट मुरादाबाद, मेरठ, एडीएम सिटी वाराणसी, सचिव विकास प्राधिकरण वाराणसी, अपर आयुक्त परिवहन लखनऊ, सचिव विकास प्राधिकरण लखनऊ के पदों पर कार्य करने के बाद वर्ष 2018 में आईएएस में पदोन्नत हुए।

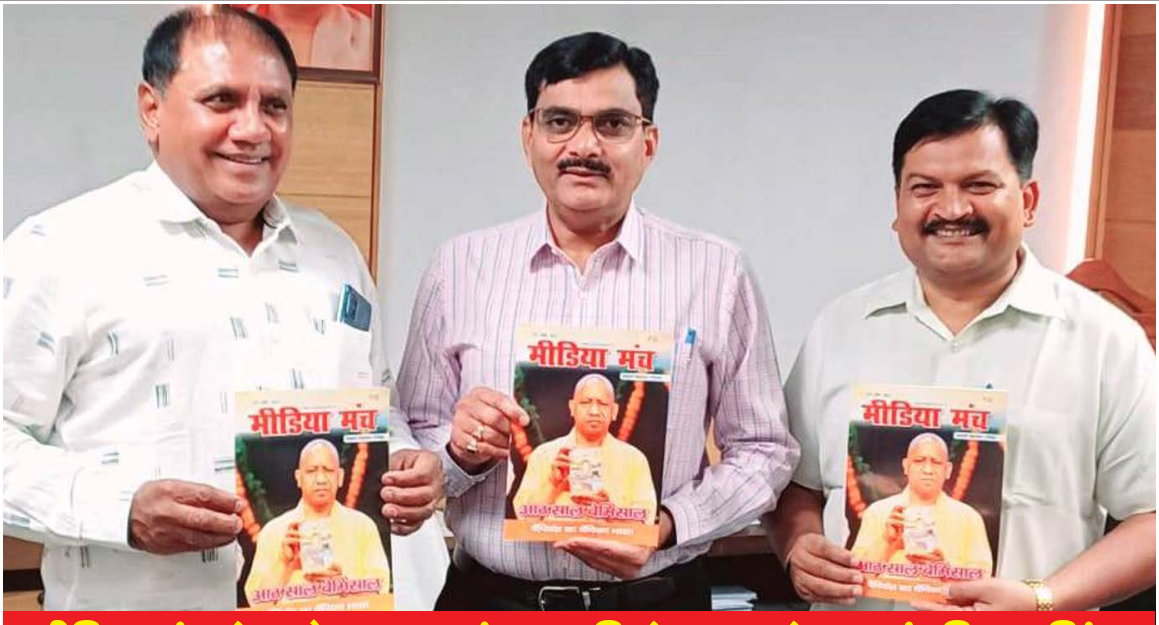

मीडिया मंच के अप्रैल, 2025 अंक का विमोचन करते IAS इंद्र विक्रम सिंह।

पाक पर प्रहार

गोविन्द पंत राजू
9415014980

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो शुरुआती कदम उठाए इनमें सिंधु जल समझौता स्थगित करना सबसे प्रमुख है। सिंधु जल समझौते को एकतरफा रोक कर भारत ने पाकिस्तान पर पाक राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहना या बाघा – अटारी बोर्डर बंद कर देना या भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तय तारीख तक भारत छोड़ने के आदेश आदि से कहीं अधिक बड़ी चोट पहुंचाई है।

1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई सिंधु जल संधि , सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को दोनों देशों के बीच बांटने का समझौता है। इस संधि में सिंधु नदी बेसिन की छह नदियों को दो भागों में बांटा गया था। पूर्वी नदियों (ब्यास, रावी और सतलज) का पानी भारत को दिया गया था, जबकि पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा कर पाकिस्तान को चौंका दिया। भारत ने कहा कि यह कदम पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को न रोकने के कारण उठाया गया है।

भारत ने कहा है कि हम सिंधु जल संधि के तहत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पश्चिमी नदियों के जल का अधिक उपयोग करेंगे।

भारत ने पहले ही सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए औपचारिक नोटिस जारी किया था और इस संधि को पुराना और पाकिस्तान के प्रति पक्षपातपूर्ण बताया था।

संधि के तहत भारत को 20 फीसदी पानी और पाकिस्तान को 80 फीसदी पानी का अधिकार मिला था। भारत को तीन पूर्वी नदियों (ब्यास, रावी, सतलज) पर नियंत्रण दिया गया था।जबकि पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) पर नियंत्रण दिया गया था।

भारत द्वारा सिंधु जल समझौता रोकने से पाकिस्तान में गंभीर जल संकट और अन्य आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं क्योंकि पाकिस्तान की अधिकांश खेती और बिजली उत्पादन सिंधु नदी प्रणाली पर आश्रित है।

पाकिस्तान की लगभग 80 फीसद खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। भारत द्वारा जल आपूर्ति बंद होने से, पाकिस्तान की कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा होगा।

सिंधु नदी पर पाकिस्तान के कई जलविद्युत परियोजनाएं हैं। जल आपूर्ति बाधित होने से बिजली उत्पादन में कमी आएगी, जिससे ऊर्जा संकट गहरा हो सकता है।

सिंधु नदी प्रणाली पाकिस्तान के कई शहरों के लिए पीने के पानी का भी मुख्य स्रोत है। जल आपूर्ति बाधित होने से, पीने के पानी की समस्याएँ उत्पन्न होंगी, जिससे सामाजिक अशांति और स्वास्थ्य खतरे बढ़ सकते हैं।

सिंधु जल समझौता पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल आपूर्ति बंद होने से, पाकिस्तान के कई उद्योग और व्यवसाय प्रभावित होंगे, जिससे आर्थिक विकास में बाधा आना तय है।

वैसे तो पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाने की घोषणा की थी लेकिन सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले की पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उपप्रधानमंत्री इसहाक डार ने पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में कहा है कि भारत इस तरह से एकतरफा फैसला नहीं कर सकता है। डार ने कहा, ''अतीत का जो हमारा अनुभव है, उससे हमें अंदाज तो था कि भारत ऐसा कर सकता है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पहले से अड़ा है। पानी रोकने के लिए उन्होंने कुछ वाटर रिजर्व भी बनाए हैं। लेकिन यह संधि बाध्यकारी है। आप इसमें एकतरफा फैसला नहीं ले सकते।''

भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित ने कहा, ''सिंधु जल संधि पर भारत एकतरफा फैसला नहीं ले सकता ।अभी भारत ने इसे स्थगित किया है। लेकिन उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वह सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी बंद कर सके। हमें तकरीबन 133 मिलियन एकड़ फिट पानी हर साल पश्चिमी नदियों से मिलता है। मुझे नहीं लगता है कि भारत इस पानी को अभी रोकने की स्थिति में है। इसलिए अभी कोई बड़ी चुनौती नहीं है लेकिन इसे रोकने के लिए हमें

सक्रिय होना होगा। मसलन चीन भी इस मामले में हमें मदद कर सकता है।चीन से कई नदियां भारत में आती हैं तो चीन भी पानी रोकने के लिए व्यवस्था कर सकता है।

पाकिस्तान के कानून मंत्री रहे अहमर बिला सूफी ने एक पाकिस्तानी टीवी चौनल से कहा, ''ये गंभीर कदम है। यह संधि बाध्यकारी है।ये एक खतरनाक फैसला है। हम इस मामले को विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेकर जा सकते हैं। पानी को डायवर्ट करना भी भारत के लिए आसान नहीं होगा। हो सकता है कि इसमें सालो लग जाएं।'' ''भारत ने एक राजनीतिक फैसला लिया है लेकिन इसका बहुत असर नहीं होगा।

वस्तुस्थिति यह है कि भारत आज भले ही रातों रात पाकिस्तान का पूरा पानी हमेशा के लिए नहीं रोक सकता, लेकिन वह अस्थायी तौर पर झेलम, चिनाब और सिंधु जैसी नदियों के पानी का फ्लो कंट्रोल करके पाकिस्तान के पंजाब के इलाके से लेकर कराची तक पानी की आपूर्ति प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, 'भारत के पास अब पानी का फ्लो डिस्टर्ब करके और उससे जुड़ी जानकारी रोककर पाकिस्तान में पानी की कमी या छोटी बाढ़ लाने की क्षमता है। पानी अचानक छोड़ा गया या रोका गया तो पाकिस्तान में दिक्कत पर दिक्कत आएगी।

भारत पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए सिंधु जल संधि को लेकर तीन चरणों में दीर्घकालिक तैयारी कर रहा है। केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि इसके लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है। सरकार शार्ट टर्म, मिड टर्म और लाग्ग टर्म के कुल तीन योजनाओं पर काम कर रही है, ताकि पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान न जाए।

पहले चरण में नई सिंधु जल संधि की जमीन तैयार करने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिए 2024 में भी भारत ने संधि में बदलाव की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस भी भेजा था। भारत सालों से नई सिंधु संधि चाहता है। इससे जलवायु परिवर्तन, पानी की मात्रा जैसे मुद्दों पर भारत अपने हित पर जोर दे सकेगा। अब भारत ने घोषित रूप से सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। अब भारत अपने फायदे का सौदा करने के लिए पाकिस्तान को बातचीत के लिए मजबूर कर सकता है।

दूसरे चरण में भारत अपने हिस्से के पानी की हर बूंद का इस्तेमाल करने के उपाय करेगा।

संधि के तहत भारत पूर्वी नदियों के 3.3

करोड़ एकड़ फीट पानी में से करीब 94 फीसदी पानी का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए भारत ने पूर्वी नदियों यानी सतलुज पर भाखड़ा नागल बांध, ब्यास पर पोंग बांध, रावी पर रंजीत सागर बांध और हरिके बैराज, इंदिरा नहर जैसे प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। बाकी करीब 6 प्रतिशत पानी बिना इस्तेमाल हुए पाकिस्तान चला जाता है। बचे हुए पानी के इस्तेमाल के लिए भारत रावी नदी पर शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, सतलुज ब्यास नहर लिंक प्रोजेक्ट और रावी की सहायक नदी पर 'उझ डैम' बना रहा है। भारत ने सुनियोजित प्लानिंग कर ली है कि वह इन नदियों का बहाव मोड़कर 100 प्रतिशत पानी अपने यहां ही इस्तेमाल करेगा।

तीसरे चरण में पाकिस्तान जाने वाले पूरे पानी को भारत की तरफ मोड़ने की योजना है जो बहुत दीर्घ कालिक योजना होगी जो सालों चलेगी। इसके लिए नदियों पर बांध और बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जाएंगे। जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाएगी। पानी को जमा करने के लिए जलाशय बनाकर नदियों की दिशा बदलने पर काम शुरू किया जाएगा।

सिंधु नदी के जलागम क्षेत्र में कश्मीर में 19 भारतीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। ये प्रोजेक्ट घाटी में बिजली उत्पादन, औद्योगिक और सार्वजनिक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जम्मू-कश्मीर की ऐसी पांच प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं में किशन गंगा जलविद्युत परियोजना किशन गंगा (नीलम) नदी पर स्थित है। यह नदी जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में झेलम नदी की एक सहायक नदी है। इस परियोजना में एक कंक्रीट राक फिल बांध शामिल है।

दूसरी प्रमुख जल विद्युत परियोजना किश्तवाड़ जिले में दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना है। चिनाब नदी पर दुलहस्ती में 65 मीटर ऊंचा और 186 मीटर लंबा कंक्रीट बांध है। 60 साल पहले शुरू हुई गंदेरबल जलविद्युत परियोजना की स्थापित और स्वीकृत क्षमता 15 मेगावाट है। परियोजना का जल स्रोत सिंध नाला है, जो झेलम की एक सहायक नदी है। यह परियोजना श्रीनगर के निकट है। उधमपुर जिले में 1975 में चालू की गई चेनानी जलविद्युत परियोजना की क्षमता 23.3 मेगावाट है। परियोजना का स्रोत तावी नदी है, जो चिनाब की एक सहायक नदी है।

पांचवीं प्रमुख परियोजना बगलिहार जलविद्युत परियोजना है, जो चिनाब नदी पर बनी है। इसका बांध 143 मीटर ऊंचा, 363 मीटर लंबा है और इसकी कुल क्षमता 900 मेगावाट है। यह परियोजना रामबन जिले में है।

जम्मू और कश्मीर में अन्य जलविद्युत परियोजनाओं में, निचली झेलम जलविद्युत परियोजना (झेलम नदी), सलाल । और ।। जलविद्युत परियोजना (चिनाब नदी), सेवा-।। जलविद्युत परियोजना (सेवा नदी), सेवा-।।। जलविद्युत परियोजना (रावी नदी), निम्मो-बाजगो जलविद्युत परियोजना (सिंधु नदी), ऊपरी सिंध जलविद्युत परियोजना (सिंध नाला नदी), उरी-। जलविद्युत परियोजना, उरी-।। जलविद्युत परियोजना (दोनों झेलम नदी पर), आदि हैं।

सिंधु जल समझौते पर फिर से बातचीत के पाक अनुरोध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। यह तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के साथ अपने संबंधों को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देता है। ❑

आतंकियों का काल

आपरेशन सिंदूर

रोहित माहेश्वरी
9450900065

आपरेशन सिंदूर का नाम पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों की नस्लें कई पुश्तें भूल नहीं पाएंगी। आतंकी ठिकानों को तहस नहस करने के लिये भारतीय सैन्य बलों द्वारा चलाए गए आपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान अपनी गलती मानने की बजाय लगातार भारतीय सैन्य ठिकानों और सिविल क्षेत्रों को अपना निशाना बना रहा है। वो तो गनीमत है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत और आधुनिक है कि वो पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान लगातार भारत को युद्ध के लिए उकसाने की हरकतें कर रहा है।

बात देश के सैनिकों की वीरता की कि जाए तो जांबाज सैनिकों का क्या निशाना था, क्या लक्ष्य चिह्नित किए गए। हमारी सेनाओं ने 6-7 मई की दरमियानी रात में 1.05 बजे से 1.30 बजे के मात्र 25 मिनट के समय में आतंकियों के 9 अड्डे मिट्टी में मिला दिए और 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया। पहलगाम नरसंहार में यहीं के आतंकियों ने हमारी बहू-बेटियों के 'सिंदूर' मिटा दिए थे। एक ही प्रतिघात में 35 साल पुराने प्रतिशोध भी ले लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 'आपरेशन सिंदूर' नाम दिया था। उनका यह कथन भी सार्थक साबित हुआ कि आतंकियों की बची-खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।

लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठनों के मुख्यालयों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। जैश के सरगना मसूद अजहर की टिप्पणी ही हमारे हमलों की आक्रामकता की पुष्टि करती है-काश! मैं भी मर जाता, तो अच्छा होता।' आपरेशन में उसकी पत्नी, बेटे, बहन-बहनोई, भांजा-भांजी, भांजे की बीवी, भतीजा आदि खानदान के 10 लोगों को भी 'मिट्टी' होना पड़ा। सरगना के करीबी 4 लोग भी मारे गए। पहलगाम में आतंकियों ने भारत की बेटियों को कहा था-तुम्हें नहीं मारेंगे। जाओ और मोदी को बता दो।'

पीएम मोदी को तो खुद एहसास था कि 'सिंदूर' मिटाया गया है, लिहाजा उनके आदेश पर सेनाओं ने साझा आपरेशन तय कर, सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर, रात के अंधेरे में 24 मिसाइलें दाग कर आतंकियों के बिल बिखेर दिए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और

फौज को भनक तक नहीं लगी। पाकिस्तान का 'डिफेंस सिस्टम' सोया ही रहा। यह फौज किस आधार पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल के दंभ भरती रही है? वाह सैनिको! तुम्हें देश का सलाम, नमन और साधुवाद! देश के लिए यह गौरव और गर्व का दिन है। हालांकि 21 आतंकी ठिकाने चिह्नित किए गए थे। अर्थात 12 आतंकी बिल अभी शेष हैं। हम अफसोस कर रहे हैं कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, सलाहुद्दीन सरीखे आतंकी सरगनाओं को जिंदा क्यों छोड़ा गया? शायद अब वे देखेंगे कि अपनों की मौत कितनी भयावह और पीड़ादायक होती है! बहरहाल अभी तो भारत की सेनाओं ने आतंकवाद का प्रथम चरण ही 'मिट्टी' किया है। आरंभ है प्रचंड, पाकिस्तान होगा खंड-खंड! आतंक के बिलों में अब भी 'सपोले' जिंदा हैं। उन्हें भी कुचलना है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है। हमारी सेनाएं और अर्धसैनिक बल फिलहाल 'सुपर अलर्ट' हैं। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बहरहाल अब हमें आतंकवाद पर स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनानी होगी। भारत पाकिस्तान को 'आतंकी देश' और 'शत्रु देश' घोषित करे। पाकिस्तान के मारे गए फौजियों के ताबूतों पर राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल मुनीर के नाम के फूल अर्पित किए गए। ताबूतों को पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर फौजियों ने सलामी दी। आतंकियों को राजकीय सम्मान से 'अलविदा' कहा जाएगा, तो पाकिस्तान की आतंकी सोच बेनकाब होती है।

इस आपरेशन से पाकिस्तान की फौज को मनोवैज्ञानिक तौर पर लकवा मार सकता है, यह विशेषज्ञों का मानना है। सेनाओं ने पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर तक हमला किया, पाक की फौज को भारत की सेनाओं की क्षमता का एहसास हो जाना चाहिए। पाकिस्तान ने कबूल किया है कि उसके 31 लोग मारे गए हैं, जबकि कई घायल हुए हैं। उसके पंजाब में आपातकाल घोषित किया गया है। हमने सिर्फ उन्हें मारा है, जिन्होंने हमारी बहू-बेटियों का 'सिंदूर' पोंछ दिया था। उन्हें 'सिंदूर' की कीमत और उसका महत्व क्या पता! बहरहाल भारतीय आपरेशन में किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान, दफ्तर और रिहायशी इलाके या इमारत को खंडित नहीं किया गया है। यह आतंकियों पर ही लक्षित आक्रमण था।

मोदी सरकार, सुरक्षा से जुड़े तमाम विभागों तथा सेना के तीनों अंगों ने बेहतर तालमेल के साथ आपरेशन सिंदूर तथा उसके बाद पाक द्वारा किए हमलों को विफल बनाने के लिये पर्याप्त होमवर्क किया। लगातार बैठकों व संवाद के जरिये इस चुनौती के मुकाबले की रणनीति को अंजाम दिया। जिससे देश के जनमानस का भरोसा बढ़ा कि देश सही हाथों में है। अब तक भारत पाक पोषित आतंकवादी हमलों के बाद सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर कार्यवाही की कोशिश करता रहा है। ऐसी स्थिति मुंबई हमले, संसद पर हुए हमले तथा पठानकोट एयर बेस पर हुए हमलों के बाद सामने आई। भारत सबूतों के आधार पर वैश्विक संगठनों से कार्रवाई की मांग करता रहा है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद आपरेशन सिंदूर को अंजाम देना नये भारत की बदली रणनीति का पर्याय ही है।

पहले पाक के परमाणु हथियार का डर दिखाकर भारत को कार्रवाई करने से रोका जाता रहा है। कालांतर में 2016 में उरी में 19 सैनिकों के मारे जाने पर नियंत्रण रेखा के पार व 2019 में पुलवामा विस्फोट के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई। इसी तरह पहलगाम हमले के बाद सीधी कार्रवाई करके साफ संदेश दिया कि किसी भी आतंकी हमले का जवाब आतंकवाद को सींचने वाले पाक पर भारत सीधी कार्रवाई करेगा। भारत ने पहले पूरी दुनिया को पुलवामा हमले की साजिश के सबूत दिए और फिर कार्रवाई की। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश भारत के पक्ष में खड़े नजर आए।

अब भारत ने महज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगाना बंद कर दिया है। निश्चय ही यह रणनीति मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के बजाय अमेरिका व इस्राइल की तर्ज पर घर में घुसकर मारने की रणनीति है। बहरहाल, भारत ने दुनिया को बता दिया कि पाक अपनी जमीन पर आतंकियों को प्रशिक्षण व समर्थन तो देता है लेकिन उनके विरुद्ध कार्रवाई से बचता है। वहीं दूसरी ओर भारत ने परंपरागत युद्ध शैली से हटकर नई तकनीकों का भरपूर उपयोग किया। भारतीय रक्षा कवच एस-400 यानी सुदर्शन चक्र आदि का पाक हमलों को विफल करना नवीनतम तकनीकों का ही प्रतिफल है।

आतंकी ठिकानों के तहस नहस होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारतीय सैन्य अड्डों और रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। भारतीय सैन्य बल उसके मंसूबों को लगातार धूल चटा रहे हैं। असल में पाकिस्तान भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है। हालांकि, भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि उसका इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है। लेकिन जवाबी कार्रवाई के लिये पूरी तरह तैयार है। इसलिए रणनीतिक संयम को विश्वसनीय प्रतिरोध के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। निस्संदेह, अब सामरिक जीत से हटकर रणनीतिक स्थिरता पर जोर दिया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में नागरिक सुरक्षा, कूटनीतिक संदेश और आंतरिक सुरक्षा पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता होगी। भारत को सुरक्षा प्राथमिकताओं से समझौता किए बिना वैश्विक भागीदारों को जानकारी देना जारी रखना चाहिए। भारत सरकार और सैन्य बल हर तरह की स्थिति से निपटने के पूर्णतः सक्षम है ये भरोस देशवासियों का है। अगर हालात युद्ध के बने तो भारतीय सैन्य बल शौर्य और वीरता का नया स्वर्णिम अध्याय युद्ध की भूमि में लिखेंगे।

सेमीकंडक्टर का 'सुपर हब' बन रहा यूपी

जेवर में जल्द स्थापित होगी नई यूनिट

यमुना एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) के सतत् प्रयासों से देश में 'आधुनिक तकनीक के उभरते गढ़' की छवि को जेवर नया आयाम दे रहा है। नोएडा में 3 नैनोमीटर की चिप डिजाइन इकाई के बाद अब जल्द ही ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर निर्माण यूनिट की भी स्थापना होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी। ग्रेटर नोएडा में 3,700 करोड़ रुपए के निवेश से दो दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियां जेवर एयरपोर्ट के समीप संयुक्त उपक्रम के रूप में लगाएंगी संयंत्र। फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद।

उत्तर प्रदेश को 'उन्नत प्रदेश' के रूप में ट्रांसफार्म कर रही डबल इंजन सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के 'एक ट्रिलियन डालर की इकॉनामी' बनाने की दिशा में मील का पत्थर रखा है। नई दिल्ली में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को स्वीकृति दी गई। डबल इंजन की सरकार द्वारा देश में सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत छठी इकाई के तौर पर इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया है। परियोजना के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के समीप दो दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों के संयुक्त उपक्रम के तौर पर 3700 करोड़ रुपए के निवेश से यूनिट को स्थापित किया जाएगा। यह सेमीकंडक्टर सेक्टर में उत्तर प्रदेश को 'सुपर हब' के तौर पर स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम सिद्ध होगा। मोदी कैबिनेट के इस फैसले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आभार जताया। सोशल मीडिया प्लैटफार्म ऐक्स पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया तथा इस निर्णय को 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में ऐतिहासिक कदम करार दिया।

यीडा अधिकृत क्षेत्र में सेमीकंडक्टर यूनिट की होगी स्थापना

मोदी कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत यूपी के ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी। यह जेवर में जल्द ही संचालित होने जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) के समीप होगा। यह नई यूनिट यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) अधिकृत क्षेत्र में स्थापित होगी जिसे दो वैश्विक दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियां संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित करेंगे।

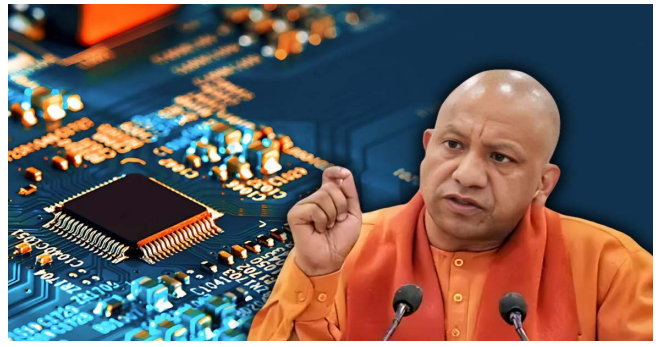

मुख्यमंत्री ने जताया प्रधानमंत्री का आभार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर हर्ष जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफार्म एक्स पर अपने आफिशियल अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा- माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी गई है जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
उन्होंने आगे लिखा, 3700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यह इकाई मोबाइल फोन, लैपटाप, आटोमोबाइल और विभिन्न उपकरणों, डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगी। भारत अब सेमीकंडक्टर विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है तथा यूपी उच्च-स्तरीय इलेक्ट्रानिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन के केंद्र के रूप में उभर रहा है।

डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का होगा निर्माण

यह संयंत्र डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगा, जो मोबाइल फोन, लैपटाप, आटोमोबाइल, पर्सनल कंप्यूटर और अन्य अनेक उपकरणों में प्रयुक्त होता है। संयंत्र की क्षमता प्रति माह 20,000 वेफर और 36 मिलियन यूनिट उत्पादन की डिजाइन क्षमता पर आधारित होगी। कुल 3,700 करोड़ रुपये के निवेश से इसे स्थापित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग तीव्र गति से विकसित हो रहा है तथा उत्तर प्रदेश भी इस कड़ी में तेजी से प्रगति कर रहा है।

यूपी की सेमीकंडक्टर नीति का दिख रहा सकारात्मक असर

यूपी ने सेमीकंडक्टर को समर्पित 'उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024' प्रख्यापित की थी जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस नीति में सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग व चिप डिजाइन के संयंत्र लगाने के लिए पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि मूल्य, स्टांप, विद्युत शुल्क में छूट के आकर्षक प्रावधान किए गए हैं जिसका लाभ दुनिया की दिग्गज कंपनियां उठाने के लिए तत्पर हैं।

भविष्य के 'सुपर हब' की छवि हो रही मजबूत

उत्तर प्रदेश चिप डिजाइन व प्रोडक्शन की दिशा में न केवल देश बल्कि विदेशों में भी भविष्य के सुपर हब के तौर पर उभर रहा है। डबल इंजन सरकार का मौजूदा प्रयास इसे और मजबूती देने का कार्य करेगा। मोबाइल फोन, लैपटाप, सर्वर, चिकित्सा उपकरण, पावर इलेक्ट्रानिक्स, रक्षा उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स के उत्पादन में तेजी से बढ़ती मांग के बीच, यह नई यूनिट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सहायक सिद्ध होगी। एक दिन पहले ही विश्व की सबसे आधुनिक चिप को डिजाइन करने वाले सेंटर की हुई स्थापना।

उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही जापान की दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ने नोएडा में अपने अत्याधुनिक चिप डिजाइन सेंटर की शुरुआत की। खास बात यह है कि यहां विश्व की सबसे एडवांस्ड 3 नैनोमीटर की चिप को डिजाइन किया जाएगा, तथा दुनिया में केवल गिनी-चुनी कंपनियों और देशों में ही इस अत्याधुनिक तकनीक पर कार्य हो रहा है। ❑

ग्रहों से उत्पन्न होने वाले रोग

आचार्य वंदना तिवारी
7048200123

जैसा की विदित है कि कुंडली में कुल नौ ग्रह होते हैं जो 12 भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं इन ग्रहों की अच्छी स्थिति में होना कुंडली को सुदृढ़ बनाता है अन्यथा कुंडली में ग्रह पीड़ित या डिग्री में कम हों तो ये कुंडली को कमजोर बनाते हैं। विशेषतः ये उन भावों को कमजोर बनाते हैं जिस भाव के इन्हें स्वामित्व मिला होता है साथ ही साथ यह उन भावों को भी कमजोर बनाते हैं जिनका ये नैसर्गिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं।

आइए देखें हमारी कुंडली कौन से ग्रह के पीड़ित होने पर कौन सी शारीरिक समस्या का संकेत देती है।

1.सूर्य ग्रह – कुंडली विश्लेषण में ग्रहों की बात की जाए तो सबसे पहले बात सूर्य की होती है सूर्य आत्मकारक ग्रह है इसे लग्न का स्वामित्व मिला रहता है अतः सूर्य का बलिष्ठ होना नितांत आवश्यक हो जाता है। नैसर्गिक रूप से सूर्य काल पुरुष की पांचवें भाव का स्वामित्व लिए हुए होता है।

सूर्य के पीड़ित होने से होने वाली बीमारी :

- व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है।
- दिमाग समेत शरीर का दायाँ भाग सूर्य से प्रभावित होता है।
- सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न आ जाती है।
- दिल का रोग हो जाता है, जैसे धड़कन का कम-ज्यादा होना।
- मुंह और दाँतों में तकलीफ हो जाती है।
- सिरदर्द बना रहता है।
- कम बालों की समस्या भी होती है।

सूर्य को मजबूत करने के उपायः

- सूर्य मंत्रों का जाप करना।
- तांबे के पात्र से सूर्य को जल चढ़ाना।
- आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना।

2. चंद्र ग्रह- चंद्रमा ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह है। यह जातक के मन, भावना और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा की स्थिति से व्यक्ति की मानसिक स्थिति, माता के साथ संबंध एवं पारिवारिक जीवन का पता चलता है।

चंद्र ग्रह से होती यह बीमारी

- चन्द्र में मुख्य रूप से दिल, बायाँ भाग से संबंध रखता है।
- मिर्गी का रोग।
- पागलपन।
- फेफड़े संबंधी रोग।
- मासिक धर्म गड़बड़ाना।
- मानसिक तनाव और मन में घबराहट।
- सर्दी-जुकाम बना रहता है

चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय

- चंद्रमा मंत्रों का जाप करना एवं चंद्रमा की पूजा करना।
- सोमवार का व्रत रखना। शिव जी की आराधना करना।
- चांदी के पात्र को प्रयोग में लाना।

2. मंगल ग्रह – मंगल ग्रह भी कुंडली में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।जातक में ऊर्जा, शक्ति और आक्रामकता का प्रतिनिधित्व मंगल के प्रभाव के कारण होता है। मंगल की सुदृढ़ स्थिति से व्यक्ति की ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास भरता है। इसके प्रभाव व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।

कमजोर मंगल से उत्पन्न रोग

- उच्च रक्तचाप।
- गठिया रोग।
- फोड़े-फुंसी होते हैं।
- गुर्दे में पथरी हो जाती है।
- आदमी की शारीरिक ताकत कम हो जाती है।
- शरीर के जोड़ काम नहीं करते हैं।
- मंगल से रक्त संबंधी बीमारी होती है।
- संतानोत्पत्ति में मुश्किलें आती है

मंगल को मजबूत करने के उपाय

- मंगल मंत्रों का जाप करना।
- हनुमान जी की पूजा करना।
- लाल रंग के वस्त्र पहनना।
- लाल वस्तुओं का दान करना।

3. बुध ग्रह – बुध ग्रह ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध के प्रभाव से जातक में बुद्धि, तर्कशक्ति की वृद्धि होती है। बुध की स्थिति से व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, संचार कौशल और व्यापारिक क्षमता का पता चलता है। इसका प्रभाव व्यक्ति की शिक्षा, लेखन और वाणी पर पड़ता है।

बुध ग्रह के पीड़ित होने पर बीमारी

- तुतलाहट।
- सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाती है।
- दाम्पत्य जीवन मे कठिनाई
- श्वसन क्रिया में तकलीफ
- पाचन तंत्र संबंधी समस्याएँ
- त्वचा संबंधी समस्याएँ

बुध को मजबूत करने के उपाय

- बुध मंत्रों का जाप करना।
- गणेश जी की पूजा करना।
- हरे रंग के वस्त्र पहनना।
- बुध के पीड़ित होने पर हर वस्तुओं का दान करें ।

जौनपुर प्रदेश में प्रथम

वीरेन्द्र सिंह

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना में जौनपुर जनपद प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। अप्रैल माह में ही ऋण वितरण के मामले में ही आगरा ने दूसरा स्थान और हापुड़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

जिलाधिकारी जौनपुर डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्ग-निर्देशन में योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए वह स्वयं धरातल पर उतरते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान को सफल बनाकर जनपद में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए डीएम खुद बैंकों में जाकर मॉनीटरिंग करते है। उन्हें दिशा-निर्देश देने के साथ-साथ जो कमियां हैं उन्हें भी दूर करते हैं। फील्ड में उतरकर योजनाओं को गति देने के इस अभियान में जिलाधिकारी सफल हैं। उनके दृढ़ संकल्प का नतीजा भी सामने आ रहा है। इसी का परिणाम है कि जौनपुर प्रदेश में पहला मुकाम हासिल किया।

इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए पांच लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर योजना का शुभारंभ किया था। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 1.5 लाख युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अप्रैल माह में आये आवेदनों में से 40635 आवेदनों को बैंक में भेजा गया था। इनमें से 9867 आवेदनों पर बैंकों ने ऋण देने की स्वीकृति दे दी है, जबकि 5838 युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन वितरित किया जा चुका है। गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 178662 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके सापेक्ष 28 हजार से अधिक युवाओं को ऋण वितरित किया गया था।

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र के सतत प्रयासों से जौनपुर जनपद अप्रैल माह में 257 युवाओं को ऋण देकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी बताते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में जिले के लिए 2200 युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आगरा ने 197 युवाओं को ऋण देकर प्रदेश में दूसरा स्थान और हापुड़ ने 167 युवाओं को ऋण देकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 7 बैंक शाखा प्रबंधकों को डीएम ने सम्मानित किया। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र और मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया ने 7 बैंक प्रबंधकों को अंगवस्त्रम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में यूनियन बैंक आफ इंडिया के तीन शाखा प्रबंधक भी शामिल हैं।

जिलाधिकारी ने बैंक के शाखा प्रबंधकों से युवाओं को रोजगार की दिशा में पूरी तत्परता के साथ कार्य करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों का योगदान सराहनीय है। उनके प्रयासों से ही जनपद को प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे भी अच्छा काम करने वाले शाखा प्रबंधकों को सम्मानित किया जाएगा और खराब प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि सीएम युवा योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्यमी बनाना और रोजगार सृजक के रूप में स्थापित करना है। इस योजना में शासन युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

सीएम युवा योजना की मुख्य बातें

- एक लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा दस वर्ष में दस लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर।
- 21 से 40 वर्ष आयु, न्यूनतम आठवीं पास की शैक्षणिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र।
- पांच लाख रूपये तक के उद्योगों / सेवा परियोजनाओं पर शतप्रतिशत ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण।

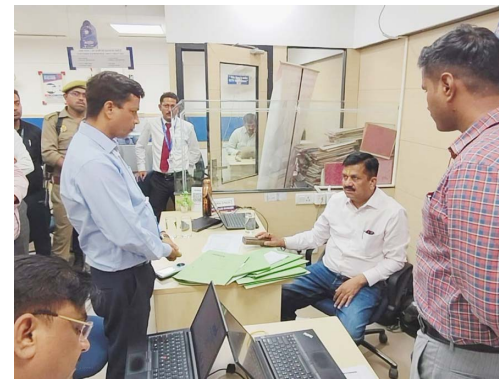

- परियोजना की लागत पर दस प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान।
- इच्छुक व्यक्ति एमएसएई.यूपी.जीओवी.इन / लागिन / रजिस्ट्रेशन पर जाकर आवदेन कर सकते हैं।
- किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर वे डीएम की जनसुनवाई कक्ष में, मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त उद्योग या एलडीएम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के आह्वान पर उ.प्र. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की मुहिम चलाई, जिससे कि अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाया जाय। जिलाधिकारी जौनपुर ने मिशन मोड में कार्य करते हुए निरंतर प्रयास किया। जिसका परिणाम है कि जनपद प्रदेश में अग्रणी रहते हुए प्रथम स्थान पर रहा।

राममंदिर पर ध्वजदंड स्थापित

राममंदिर की कुल ऊँचाई 203 फिट हुई

तेज बहादुर सिंह

सहसा विश्वास नहीं होता कि 500 सालों के संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस तरह हर राम भक्त की मनोकामना पूरी हो चुकी है। रामलला के दर्शन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।

दिव्य-भव्य और अलौकिक राम मंदिर 56 महीने में बनकर 1200 करोड़ की लागत के खर्च के साथ तैयार हुआ है। नागरशैली में बने राममंदिर में वंशी पहाड़पुर के करीब 4.50 लाख क्यूबिक लाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। संपूर्ण राममंदिर तकनीक व स्थापत्य कला का अदभुत संगम है। संपूर्ण राम मंदिर का निर्माण भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है।

उल्लेखनीय है कि लंबे कानूनी विवाद के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया था। नागरशैली में निर्मित यह मंदिर 380 लंबा, 250 फिट चौड़ा और 161 फिट ऊँचा है। तीन मंजिले इस मंदिर में कुल 392 स्तंभ हैं जो प्राचीन भारतीय शिल्पकला की गौरवगाथा कहते हैं।

ध्वजदंड की स्थापना के बाद मंदिर की ऊँचाई हुई 203 फिट

बैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि (29 अप्रैल 2025) को भगवान परशुराम जयंती के शुभ पावन दिन पर प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर के मुख्य शिखर पर 42 फुट ऊँचा दिव्य ध्वजदंड के विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा के साथ ही रामनगरी एक बार फिर ऐतिहासिक क्षणों की गवाह बनी।

वैदिक आचार्यों की मौजूदगी में विधि-विधान के साथ मुख्य शिखर पर स्थापित ध्वजदंड 42 फिट ऊँचा है। जबकि राममंदिर की 161 फिट ऊँचे शिखर पर कलश की स्थापना हुई और जब शंखनाद और वेदमंत्रों की गूंज के बीच ध्वजदंड मंदिर के शिखर पर सीपित हुआ तो जैसे संपूर्ण अयोध्या की आत्मा श्रीराम के जयघोष से आकाश को स्पर्श कर गई। शिखर कलश समेत जहां मंदिर की कुल ऊँचाई 161 फिट थी तो वहीं अब 42 फिट के ध्वजदंड की स्थापना के साथ मंदिर की कुल ऊँचाई 203 फिट हो गई है।

ध्वजदंड जब मंदिर के शिखर पर स्थापित हुआ तो जैसे हरभक्त का हृदय भी गर्व से भर उठा। यह केवल एक धातु का स्तंभ नहीं है बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था, श्रद्धा और स्वाभिमान का प्रतीक है। मुख्य शिखर पर ध्वजदंड की स्थापना के साथ गर्भगृह का उपरी हिस्सा भी पूरा हो गया है।

मंदिर परिसर में सप्त ऋषियों के सात मंदिर और परकोटा के 6 देवी-देवताओं के मंदिरों का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। सप्त ऋषि मंदिरों में मूर्तियां सीपित की जा चुकी हैं।

राममंदिर निर्माण के मुख्ख पड़ाव

- 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से राममंदिर के हक में फैसला दिया।
- 25 मार्च 2020 की सुबह टेंट से अस्थाई मंदिर में रामलला विराजे।
- 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों भूमि पूजन।
- 22 जनवरी 2024 को भव्य राममंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा।
- 14 अप्रैल 2025 को मुख्य शिखर पर

ध्वजदंड की खास बातें

- चौड़ाई- 9.5 इंच, उंचाई-42 फुट, वजन- 5.5 कुन्टल।
- अहमदाबाद के 40 कारीगरों ने 9 महीने में इसे तैयार किया।
- ध्वजदंड की संरचना कांस्य से तैयार की गई है।
- आंधी-तूफान से ध्वज को कोई नुकसान नहीं होगा।
- ध्वजदंड का निर्माण गुजरात की भरत भाई कंपनी ने विशेष डिजाईन के साथ तैयार किया जो मंदिर की पवित्रता और भव्यता के अनुरुप है।

जबकि परकोटा के मंदिरों में चार शिखर कलश लग चुके हैं।

तीनों तल का निर्माण कार्य पूरा

राममंदिर के तीनों तल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दिसंबर 2025 तक मंदिर समेत अन्य प्रकल्पों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। पहले तल पर जल्द ही राम दरबार की स्थापना कर दी जाएगी। दिसंबर के अंत तक राम मंदिर का सारा काम पूरा हो जाएगा। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है।

प्राण-प्रतिष्ठा का एक और दौर चलेगा

राम मंदिर में एक बार फिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है। इस बार शेषावतार मंदिर, सप्त मंडपम व परकोटा के मंदिरों में विराजमान होने वाली मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा होनी है।

प्राण-प्रतिष्ठा समारोह तीन से 5 जून तक होनी है। 5 जून को गंगा दशहरा पर सभी मंदिरों में एक साथ मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा होगी। वैसे परकोटा और सप्त मंडपम की मूर्तियां मंदिरों के आसान पर विराजमान हो गई हैं।

शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित की जाएगी। मूर्ति करीब साढ़े चार फिट ऊँची है। वनवासी वेष में लक्ष्मण की मूर्ति को संगमरमर के पत्थर पर आकार दिया गया। राजस्थान के जयपुर से मूर्ति बन कर आई है।

राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र के अनुसार अब राम मंदिर के आसपास मात्र कुछ हजार क्यूबिक फिट पत्थर और लगने बाकी हैं। परकोटा के निर्माण का काम तेज कर दिया गया है। परकोटा के 6 मंदिरों के कलश का भी पूजन और सीपना हो चुका है। राम कथा संग्रहालय के निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। प्रयास है कि अगले तीन महीने में संग्रहालय की कम से कम पांच गैलरी तैयार हो जाए। जिससे श्रद्धालु उसका भी दर्शन कर सकें। ❑

मीडिया मंच के सम्पादक तेज बहादुर सिं

ह के वैवाहिक जीवन का ''स्वर्ण जयन्ती'' समारोह !

मैं काशी का कर्जदार

वीरेन्द्र शुक्ल

अपने संसदीय क्षेत्र काशी के 50वें दौरे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा 'मैं काशी के प्रेम का कर्जदार हूं।'

उन्होंने काशीवासियों से कहा कि जब काशी ने हमें तीसरी बार आशीर्वाद दिया तो हमने भी सेवक के रूप में स्नेह स्वरूप कर्तव्य निभाया और कुछ लौटाने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि 10 वर्षों में काशी के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। इन 10 वर्षों में काशी ने आधुनिक समाज को साधा और विरासत को भी संजोया है। साथ ही उज्ज्वल बनाने की दिशा में भी मजबूत कदम रखें हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, प्रगतिशील भी है। बीच-बीच में प्रधानमंत्री ने काशिका में संबोधन से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया।

प्रधानमंत्री का जाम मुक्त काशी पर विशेष जोर रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में चार बार जाम से मुक्ति के लिए सड़क, फ्लाईओवर आदि के विस्तार की बात कही। कहा कि किस तरह विकास कार्यों के जरिए शहर को जाममुक्त बनाया गया। इसी बहाने उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर तंज भी कसा। वे बोले कि आज हर दिन हजारों लोग बनारस आते हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। मां गंगा में स्नान करते हैं। हर यात्री कहता है कि बनारस बहुत बदल गया है। कल्पना कीजिए अगर काशी की सड़कें, यहां की रेल और एयरपोर्ट की स्थिति 10 साल पहले जैसी ही रहती तो हालत कितनी खराब हो गई होती। पहले तो छोटे-छोटे त्योहारों के दौरान भी जाम लग जाता था। उन्होंने चुनार से शिवपुर के बीच आवागमन के लिए फुलवरिया फोर लेन की सुविधा का नाम लिया। बताया कि अब शहर से होकर शिवपुर नहीं जाना पड़ता। बावतपुर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, रिंग रोड, हाईवे निर्माण आदि से बनारस के साथ ही जौनपुर, गाजीपुर आदि जिलों के लोगों को भी सहूलियत का भी उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा कि जहां पहले जाम था, आज वहां विकास की रफ्तार है।

मोदी ने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि ढांचागत विकास को और बेहतर बनाने के लिए आज भी हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रांस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स,

"काशी हमार हय, हम काशी के हई... जौने काशी के स्वयं महादेव चलवलन, आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो।

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

जीआई टैग में देश में पहले नंबर पर यूपी

प्रधानमंत्री ने जीआई उत्पाद बनारसी लाल पेड़ा, मेटल कास्टिंग, क्राफ्ट, शहनाई, तिरंगी बर्फी, ठंडाई समेत उत्तर प्रदेश के 21 उत्पादों को जीआई टैग का प्रमाण पत्र दिया। जीआई टैग के बारे में जीआई विशेषज्ञ डॉ. रजनीकांत का कहना है कि कुल 77 जीआई उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। इसमें कुल 32 जीआई के साथ काशी क्षेत्र दुनिया के जीआई हब के रूप में जाना जाता है। 20 लाख लोगों का जुड़ाव और 25500 करोड़ का वार्षिक कारोबार अकेले काशी क्षेत्र से होता है।

वाराणसी की दो विशिष्ट पहचान बनारसी तबला और भरवा मिर्च भी अब जीआई टैग प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्पाद बन गए हैं।

संगीत प्रेमियों के लिए बनारसी तबला वर्षो से एक खास स्थान रखता है। वहीं बनारसी भरवा मिर्च अपने अनूठे स्वाद और पारंपरिक विधि के कारण मशहूर है। चिरई गांव के करौंदे को भी जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

गांव-गांव और घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल सुविधाओं का विस्तार, हरक्षेत्र हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं, पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी पर करीब 45 हजार करोड़ रूपये खर्च हुए हैं।

राजा तालाब के मेहंदी गंज में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री ने 3884 करोड़ की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का लाभ बनारस के अलावा पूर्वांचल के विभिन्न जिलों को भी मिलेगा। उन्होंने आयुष्मान वयवंदना योजना के तीन लाभार्थियों को कार्ड और तीन शिल्पियों को जीआई प्रमाण पत्र सौंपा।

बुजुर्गों से बोले, बिना पैसे उपचार कराइए

साथ ही उन्होंने सभी बुजुर्गों से कहा कि आयुष्मान वयवंदन योजना का लाभ लीजिए। पांच लाख तक का निःशुल्क इलाज है। अब बिना पैसे इलाज कराइएगा।

इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक, बनारस डेयरी के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी भी मौजूद थे।

इस बार वह अपने संसदीय क्षेत्र में दो घंटे 53 मिनट तक रहे। जनसभा को संबोधित करने के साथ ही साथ उन्होंने करीब 15 मिनट तक भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर हर हर महादेव का घोष किया। ❑

11 वर्षों में बदला काशी का कलेवर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी आगमन पर उनका आभार जताते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में काशी का जो विकास हुआ है उस नई काशी और उसके नए कलेवर को देखने के लिए हर कोई उतावला दिख रहा है। हर किसी ने बदलती हुई काशी को देखा है। यह वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी। अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा का प्रचीन केन्द्र रही है। लेकिन अस्त-व्यस्त पड़े शिक्षा के केन्द्रों के साथ ही स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्षों में यहां 50,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाएं आई हैं।

यूपी के उत्पादों को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान

उन्होंने कहा कि काशी और उत्तर प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयास सार्थक साबित हुए हैं। स्थानीय हस्तशिल्पियों और कारीगरों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए गए हैं। यही नहीं आयुष्मान भारत एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित हुआ है। देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग तो उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे-सीधे लाभान्वित हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राधा-कृष्ण की लीलाओं से आच्छादित अंग वस्त्र पहनाकर और स्मृति चिन्ह के रूप में वाराणसी की जीआई टैग प्राप्त काष्ठ कला से निर्मित छत्र भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया।

गरीबी मुक्त गांव में दिख रही आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर

जालौन का रगौली गांव न केवल प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गांव ही बना है बल्कि इस गांव में अब आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी नजर आ रही है। यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि सभी योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया गया। जिससे ग्रामीणों को रगौली में ही रोटी-कपड़ा और मकान मिलने लगा है। जिससे यहां के लोगों को कमाने के लिए गांव की दहलीज नहीं लांघनी पड़ रही है। यहां की कई पीढ़ियों ने गरीबी से आजाद होने का जो सपना देखा था उसे अब प्रशासन ने सच कर दिखाया है। अब यहां का हर परिवार अच्छी आय के साथ अच्छा जीवन यापन कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो पावर्टी मिशन के तहत इस गांव को चुना था और पिछले साल महात्मा गांधी की जयंती पर उन्होंने जीरो पावर्टी मिशन को लांच किया था। 2200 आबादी वाले इस रगौली गांव से गरीबी का नामो निशान मिट चुका है। जबकि इस अभियान के तहत पूरे राज्य में 25 लाख गरीब परिवारों को गरीबी से दलदल से निकालने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत जिले में 12 हजार से ज्यादा ऐसे परिवारों को चुना गया। इसके तहत रगौली गांव के तहत 705 परिवारों का प्रशासन ने सर्वे कराया। सभी को सरकारी योजना के जरिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई।

इसमें 22 परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। इस पर डीएम राजेश कुमार पाण्डेय ने इन परिवारों को इस मिशन से जोड़ने का काम शुरू किया। सभी 22 परिवारों के एक-एक सदस्य को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ट्रेनिंग मुहैया कराई गई। ट्रेनिंग के दौरान परिवार के कुछ सदस्यों को दूसरे राज्यों में रोजगार मुहैया कराया गया। कुछ तो राजस्थान जैसे जिले में 22 हजार रूपये तक कमा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गांव के युवाओं को चार लाख रूपये तक का लोन दिलाया गया।

गांव के प्रधान फुलेरा पंचायत (वेब सीरीज) की तरह किसी जन प्रतिनिधि की ओर नहीं ताकते हैं। बल्कि अपने गांव के लिए सीधे प्रशासन का दरवाजा ही खटखटाते हैं। यही वजह है कि खेती-किसानी से लेकर मेहनत, मजदूरी और व्यापार सभी के इंतजाम की जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने संभाल रखी है।

डकोर ब्लाक का रगौली गांव शहर से जुड़ा है। यहां भी कुछ समय पहले तक अन्य गांवों की तरह तमाम सुविधा-संसाधन नहीं थे। हाल ही में जिला प्रशासन ने रगौली की सुध ली। इसके जीरो पावर्टी योजना में शामिल किया गया। धीरे-धीरे गांव की सूरत बदलने लगी। प्रशासन ने सबसे पहले खेती की सुध ली। किसानों की सिंचाई की चिंता खत्म करने के लिए तालाब में स्प्रिंकलर सेट लगवाए गए। साथ ही गांव के 350 युवाओं को मनरेगा से जोड़कर 700 हाथों को रोजगार दिया गया। इससे उन्हें बच्चों की शादी व दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलने लगा। गांव के 22 लोगों के लिए प्रशासन ने पीएम आवास भी स्वीकृत कर दिया है।

क्या है जीरो पावर्टी योजना?

यूपी सरकार की तरफ से जीरो पावर्टी मिशन के तहत गरीब परिवारों को भोजन, कपड़े, शिक्षा, मेडिकल सुविधा और आवास जैसी जरूरतों को पूरा किया जाता है। मिशन के तहत हर गांव से निर्धन परिवारों को चुनाव होता है।

इन परिवारों को कई कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाया जाता है। अभियान का उद्देश्य है कि हर परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1.25 लाख रूपये पहुंच जाए।

जालौन जिले के 574 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण में 45 गांव का चयन किया गया था। इसमें रगौली गांव भी शामिल था। रगौली के बाद अब अन्य गांवों में भी सर्वे किया जा रहा है।

Garden BAY CROWN

Project RERA No.: **UPRERAPRJ557069**
Promoter RERA No.: **UPRERAPRM10366**
www.up-rera.in

CROWN YOUR LIFE.

The city's most admired lifestyle is now just a *Green Corridor* away.

Artistic Impression

Gated Community

Clubhouse for leisure & gatherings

Private Balconies with serene views

Jogging Tracks

24x7 Security

Located at Sitapur-Hardoi Road Junction,
Garden Bay Crown keeps you close to Hazratganj via the
New Green Corridor

LIVE GRAND. LIVE CROWN.

Bank A/c Name:- SHALIMAR KSMB PR COL AC GARDEN BAY CROWN | A/c No: 50200075256662
Branch : HDFC BANK, PRANAY TOWERS, HAZRATGANJ,LUCKNOW | Bank: HDFC BANK

KSMB Creating Infrastructure

SHALIMAR

To Book your exclusive visit call :
95133 15867

Corporate Office : Shalimar Corp Limited, Titanium, Shalimar Corporate Park, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
E: sales@shalimar.org | **W:** shalimarcorp.com

आस्था की डगर पर चारधाम यात्रा

देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा की शुरूआत होने के साथ ही देश-दुनिया से तमाम श्रद्धालु यहां आकर आस्था की डगर पुण्य लाभ कमाने की कामना में लीन हो गए हैं।

सबसे पहले चारधाम यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुआ। 30 अप्रैल को पहले अभिजीत मुहुर्त में सुबह 10:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट पूर्वाह्न 11:55 बजे रोहिणी नक्षत्र सिद्धि योग में खोले गए।

इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद दोनों धामों में उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रीन और क्लीन चारधाम यात्रा के आयोजन के लिए लोगों से सहयोग की अपील की और कहा कि 'अतिथि देवो भव' की भावना से सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाए। कपाट खुलने के बाद दोनों धामों के मंदिरों के उपर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा ने श्रद्धालुओं का उत्साह दोगुना कर दिया।

इसके बाद दो मई को 11वें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट भी पूरे विधि-विधान से खोले गए। कपाट खुलने पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई। हर हर महादेव के जयकारे और सेना के ग्रेनेडियर रेजीमेंट के बैंड की धुनों के बीच बाबा केदार के कपाट खुले। इस मौके पर बाबा केदार के धाम को 108 कुंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया था। इस मौके पर 15 हजार से ज्यादा श्रद्धालु केदारधाम में मौजूद थे।

सबसे अंत में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। इसी के साथ चारधाम यात्रा पूरी तरह विधिवत शुरू हो गई। कपाट खुलने के बाद कुछ ही घंटे में 10 हजार से ज्यादा श्रद्धालु धाम में पहुंचे। श्रद्धालु अगले 6 महीने तक बद्रीविशाल के दर्शन कर पाएंगे। तीन मई को भगवान बद्री विशाल की पालकी, आदि गुरू शंकराचार्य की गद्दी, कुबेर और उद्धव की उत्सव डोली धाम पहुंची थी।

यमुनोत्री धाम की तरह ही श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद तप्तकुंड में स्नान करके भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बर्फीले पहाड़ों से घिरे बद्रीनाथ धाम में मौजूद तप्तकुंड में अलखनंदा नदी के जल की गर्म धारा आती है। मान्यता है कि जो भी तप्तकुंड में स्नान कर भगवान बद्रीविशाल के दर्शन करता है, उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होता है।

धाम के कपाट खुलते ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे मंदिर परिसर को सिक्योरिटी जोन में ले लिया गया है। बद्रीनाथ धाम मंदिर की सुरक्षा में गढ़वाल राइफल्स, एसडीआरएफ, पीएसी और एलआईयू के 500 जवान तैनात किए गए हैं।

बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी केरल के नम्बूदरी ब्राहम्ण होते हैं। जिन्हें रावल कहा जाता है। पिछले साल तक ईश्वर प्रसाद नम्बूदरी मुख्य रावल थे। लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने पद छोड़ दिया है। इस बार 30 साल के अमरनाथ नम्बूदरी को नए रावल की जिम्मेदारी मिली है। वे 24वें रावल हैं जो बद्रीनाथ धाम में 250 साल पुरानी इस परंपरा को जारी रखेंगे। आठवीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य ने चारों धामों में चार पीठों की स्थापना की थी तो उन्होंने बद्रीनाथ में पूजा की जिम्मेदारी केरल के नम्बूदरी ब्राहम्णों को दी थी।

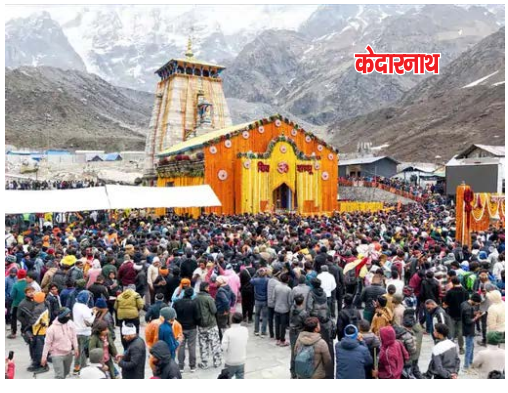

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

चार धाम यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा रूट पर करीब 6 हजार पुलिसकर्मी, पीएसी की 16 कंपनियां और अर्द्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। पूरे यात्रा क्षेत्र को 15 सुपर जोन में बांटा गया है।

अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन अब भी जारी है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के पहले एक महीने तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। ❑

आला अफसरों को खड़ा कर CM सुनते रहे जनता की फरियाद

जन समस्याओं के निस्तारण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल गहरी रूचि ही दिखलाते हैं बल्कि उनकी समस्याओं का जल्दी और सही निस्तारण हो इसके लिए भी वे सचेष्ट रहते हैं। इसी की बानगी पिछले दिनों देखने को मिली। जब उन्होंने जनता दर्शन में जनता की फरियाद सुनते वक्त न केवल खुद ही खड़े रहे बल्कि इस दौरान उन्होंने शासन के उन आला अफसरों को भी वहां खड़ा रखा जिन पर जनता तक निर्वाध सुविधाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी है।

दरअसल जन सुनवाई पोर्टल की समीक्षा के दौरान खासतौर पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिले व तहसील स्तर के मामले नीचे सही सुनवाई न होने के चलते ही पीड़ित जनता अपना दुखड़ा सुनाने और समुचित समाधान के लिए शासन के द्वार आ जाती है। इस तरह जनता को दिक्कत होती है और वहीं शासन की मंशा भी प्रभावित होती है।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल के मध्य में उन्होंने जनता दर्शन में बैठे 112 फरियादियों की समस्याएं न केवल खुद खड़े-खड़े सुनीं बल्कि आला अफसरों को भी खड़ा रखा ताकि उनकी शिकायतें सीधे आला अफसरों तक पहुंचकर समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव मनोज कुमार सिह, डीजीपी प्रशांत कुमार, अपर मुख्य सचिव सीएम एसपी गोयल, राजस्व परिषद चेयरमैन अनिल कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद आदि मौजूद रहे। सीएम ने जनता की शिकायतें सीधे इन्हीं अफसरों को सौंपी।

इस तरह मुख्यमंत्री ने आला अफसरों को जनता के सामने खड़ा कर इसका आईना भी दिखाया। यही नहीं मुख्यमंत्री ने अफसरों को संवेदनशील होने व समस्याओं के समयबद्ध समाधान की नसीहत भी दी। मुख्यमंत्री के समक्ष 112 लोगों ने अपनी समस्याओं के 88 प्रार्थना पत्र रखे। योगी ने व्यक्तिगत तौर पर सबकी बात सुनी व कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वरासत, अवैध कब्जा, पैमाइश से संबंधित 23 आवेदन राजस्व परिषद के अध्यक्ष को सौंपे। पुलिस से जुड़े 23 प्रकरणों में डीजीपी को कार्रवाई के निर्देश दिए। विवेकाधीन कोष, शादी अनुदान आदि से संबंधित 17 आवेदन अपर मुख्य सचिव सीएम को सौंपे। 25 अन्य मामले मुख्य सचिव को तत्काल कार्रवाई के लिए दिए।

उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को बेहतर मैकेनिज्म बनाने के लिए भी कहा। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी अधिकारी सुबह 10 बजे से कार्यालय में बैठें और जन शिकायतें सुनें।

पूर्व IAS रमारमण से घंटो पूछताछ

पूर्व आईएएस रमारमण के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण घोटाले में उनसे लंबी पूछताछ हुई है।

ईडी ने नोएडा प्राधिकरण में हुए घोटाले में जिस दूसरे और रिटायर आईएएस व पूर्व सीईओ से पूछताछ की है, वह रमारमण हैं। रमारमण से पूर्व नोएडा अथारिटी के पूर्व सीईओ मोहिन्दर सिंह से भी ईडी लंबी पूछताछ कर चुकी है।

लखनऊ जोनल मुख्यालय की टीम ने उनसे घंटों पूछताछ की। ईडी ने उनकी व बच्चों की सम्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा लिया गया। साथ ही नोएडा प्राधिकरण घोटाले में हुए फर्जीवाड़ा को लेकर कई सवाल पूछे गए।

रमारमण ने पूर्व आईएएस मोहिन्दर सिंह की ही तरह दूसरे अफसरों पर ही सारा ठीकरा फोड़ा है। जबकि उन्हीं के कार्यकाल में घोटाले हुए थे।

रमारमण नोएडा अथारिटी में तीन साल से अधिक समय तक सीईओ रहे और उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अगस्त 2016 में उन्हें उनके पद से हटाया गया था।

इस तरह देखा जाए तो हैसिंडा प्रोजेक्टस प्राईवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों, निदेशकों व संबंधित संस्थाओं द्वारा लोटस 300 प्रोजेक्ट्स के जरिए निवेशकों से 426 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में अब ईडी की कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है। ईडी अब रिटायर्ड आईएएस मोहिन्दर सिंह के बाद अथारिटी में 2010 से 2016 तक तैनात रहे अफसरों की भूमिका की जांच में लगा हुआ है।

मोहिन्दर ने ईडी को दिए बयान में बताया है कि 2010 में वह सीईओ के पद से हट गए थे। प्रोजेक्ट से जुड़ी बाकी औपचारिकताएं उनके बाद तैनात रहे अफसरों के कार्यकाल में पूरी हुईं।

जहां तक रमारमण की बात है तो वह सपा सरकार में वह ताकतवर अफसरों में शुमार थे। वह तीन साल तक इस पद पर रहे। इसके साथ ही उनके पास ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के अध्यक्ष का भी चार्ज था। वर्ष 2016 में उनकी तैनाती को लेकर विपक्ष ने काफी शोर मचाया था। उसी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें पद से हटाया गया था।

DM की अध्यक्षता में हर जिले में बनेगा 10 खरब डॉलर सेल

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिला ओटीडी (दस खरब डॉलर) सेल के गठन को लेकर सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस तरह सभी जिलों में दस खरब डॉलर सेल बनाए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कई रणनीतिक और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला ओटीडी (वन ट्रिलियन डॉलर) सेल के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

इस सेल का उद्देश्य जनपद स्तर पर दस खरब डॉलर योजना के तहत हो रहे कामकाज की समीक्षा और सरकार को भेजे जाने वाले आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के साथ जिलों के योगदान में तेजी लाना है।

उन्होंने बताया कि जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी इस सेल के सदस्य संयोजक और इससे संबंधित जिलास्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी जिले के शिक्षाविद व उद्योगपति आदि को समिति में सदस्य रख सकते हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि सेल के द्वारा फसलों, औद्योगिक फसलों के उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और प्रोसेसिंग, उद्योगों के लिए जमीन आवंटन और स्वीकृति की स्थिति, औद्योगिक इकाईयों की स्थापना व उनके कार्यशील होने और संबंधित इकाईयों के पंजीकरण की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा राजमार्गों, विद्युत ग्रिड, लॉजिस्टिक्स हब, विशेष निवेश जोन, टाउनशिप, औद्योगिक क्षेत्र, प्लेज पार्क आदि अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा।

क्या यूपी को मिलेगा फुल टाइम DGP ?

उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में क्या उनके बाद प्रदेश को नया डीजीपी, वह भी फुल टाइम मिलेगा ?

उल्लेखनीय है कि पिछले तीन साल से प्रदेश की पुलिस मुखिया की बागडोर डीजीपी ही संभालते आए हैं। यदि प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिला तो बहुत संभव है कि प्रदेश को फुल टाइम डीजीपी मिल जाएगा ? यद्यपि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के बाद मुख्यमंत्री योगी ने यूपी पुलिस की सराहना की थी और यह भी सर्वविदित है कि प्रशांत कुमार को योगी का करीबी अफसर माना जाता है। इसके अलावा प्रशांत कुमार कड़क और सुर्खियों में रहने वाले पुलिस अधिकारी हैं।

2017-18 में उन्होंने पहली बार उस समय सुर्खियां बटोरी थीं जब कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कराई थी। साथ ही मेरठ जोन के एडीजी रहते हुए अपराधियों पर सख्ती से भी वह चर्चा में आए थे। यही नहीं अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक पर कार्रवाई के बाद वह ठोंक दो नीति के चेहरे के रूप में उभरे थे। उन्हें सेवाविस्तार मिला तो वह भी मात्र तीन महीने को होगा और यह केन्द्र सरकार की अनुमति से ही संभव होगा।

वैसे कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीजीपी बनने की रेस में हैं। इस रेस में सबसे पहला नाम वरिष्ठ आईपीएस राजीव कृष्ण का सामने आ रहा है। 1991 बैच के आईपीएस राजीव फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष और विजिलेंस के निदेशक भी हैं। दूसरे नंबर पर दलजीत सिंह चौधरी का नाम है। वह वर्तमान में बीएसएफ के डीजी हैं। उनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह से अधिक का समय है।

वर्तमान में एसपीजी की कमान संभाल रहे आलोक शर्मा भी इस रेस में हैं। इसी तरह 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी एम.के. बसाल भी रेस में शामिल हैं।

अजय कुमार बने UPSC के नए चेयरमैन

पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएसएस) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सिविल सेवा और एनडीए जैसी अहम परीक्षाएं आयोजित करने वाले यूपीएससी को नया चेयरमैन मिल गया है। अजय कुमार के पहले प्रीति सूदन यूपीएससी की चैयरमैन थीं और उनका कार्यकाल 29 अप्रैल 2025 को खत्म हुआ था।

अजय कुमार 1985 बैच के केरल कॉडर के आईएएस अधिकारी हैं। रक्षा मंत्रालय में सचिव रहते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण रक्षा सुधारों में भूमिका निभाई थी। अजय कुमार ने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल कर रखी है।

अनिल कुमार बने आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष

वरिष्ठ आईएएस और राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार-।। को उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके नाम की घोषणा होते ही नौकरशाही और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस जिम्मेदारी को संभालते हुए वह अब राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन का नेतृत्व करेंगे। वह 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं।

30 अप्रैल को मोनिका एस गर्ग के रिटायर होने के साथ ही आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद खाली हो गया था।

अनिल कुमार की गिनती राज्य के अनुभवी और भरोसेमंद अधिकारियों में की जाती है। वह कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमता और दक्षता को व्यापक सराहना मिलती रही है। बतौर राजस्व परिषद अध्यक्ष उन्होंने भूमि, राजस्व एवं ग्रामीण मामलों में कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इस नियुक्ति को न केवल प्रशासनिक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। बल्कि नौकरशाही में एक सकारात्मक नेतृत्व के आगमन के तौर पर भी।

उनसे एसोसिएशन के सचिव पंकज कुमार ने मिलकर उन्हें अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करवाया। पंकज कुमार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पंकज कुमार ने उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में आईएएस एसोसिएशन और अधिक संगठित, सशक्त और नीतिगत सहयोगी बनेगा।

आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद भार उसे ही मिलता है जो मुख्य सचिव और सीएम आफिस के बाहर तैनात सर्वाधिक सीनियर आईएएस अफसर होता है।

8 सालों से नहीं हो पाया है आईएएस वीक

अनिल कुमार द्वितीय के यूपी आईएएस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना भले ही गर्व की बात है लेकिन यह ताज कांटों भरा है।

कारण यह कि पिछले आठ सालों से आईएएस वीक नहीं हो पाया है। अफसरों को लेकर कई मुद्दे बीच-बीच में आते रहे लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से केवल एक बार ही एसोसिएशन की बैठक हो पाई। कहने के लिए संगठन है, अध्यक्ष भी हैं और सचिव भी हैं। लेकिन यह सब एक रश्म अदायगी भर है। क्योंकि सात साल पहले ही हर साल आईएएस वीक होने वाली परंपरा टूट गई।

कभी यूपी आईएएस एसोसिएशन काफी बलशाली हुआ करता था। यूपी आईएएस एसोसिएशन ने ही सबसे भ्रष्ट अफसर का चुनाव किया था। तब एसोसिएशन की ताकत का ही नतीजा था कि संगठन के सदस्यों ने वोट से टॉप 5 भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों को चुनाव किया था। देशभर में इस पहल की बड़ी चर्चा हुई थी। विजय शंकर पांडेय ने यह पहल की थी। उनके साथी आईएएस अफसरों ने उनका साथ दिया था। जिससे भ्रष्ट अधिकारियों का चुनाव हुआ था। लेकिन अब एसोसिएशन निष्क्रिय नजर आता है। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। सब अपनी-अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। किसी के चक्कर में एसोसिएशन निष्क्रिय पड़ गया है। वरना आईएएस वीक के दौरान मीटिंग, डिनर आदि के साथ सीएम इलेवन और आईएएस इलेवन के बीच दोस्ताना क्रिकेट मैच भी होता था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बार इस तरह के मैच में बल्लेबाजी की थी।

जस्टिस बीआर गवई देश के 52वें CJI

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उन्होंने 14 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया। संजीव खन्ना के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर होने के बाद उन्हें यह पद मिला है।

उल्लेखनीय है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 16 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस गवई के नाम की अनुशंसा की थी। उसी के क्रम में विधि मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर जस्टिस गवई को भारत के 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की।

6 महीने का होगा कार्यकाल

जस्टिस बीआर गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। 23 दिसंबर को 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर जस्टिस गवई का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के बाद शीर्ष अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। यह नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की गई है।

सनातन से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान : दीपक

प्रदेश की शिखर की नौकरशाही यानी मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्ति के बाद दीपक सिंघल ने अपने को सनातन से जोड़ा है। इसके लिए उन्होंने भारतीय संस्कृति वैश्विक न्यास की स्थापना की।

दीपक सिंघल के अनुसार उन्होंने न्यास की स्थापना करना इसलिए जरूरी समझा है कि इसके माध्यम से आमलोगों को यह बताना है कि पूरे विश्व की सभी जटिल समस्याओं का समाधान सनातन से ही मुमकिन है। पूरी दुनिया को सनातन से अवगत कराने के लिए उन्होंने 75 देशों की यात्रा कर सनातन की अलख जगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उनके इस न्यास में 200 से ज्यादा प्रोफेसर व विचारक जुड़े हुए हैं। इस न्यास में दीपक सिंघल के अलावा अन्य प्रमुख लोगों में प्रोफेसर कपिल कपूर, प्रोफेसर जगवीर सिंह, प्रोफेसर रजनीश मिश्रा, डॉ. मनमोहन शिंदे, डॉ. गंगोपाध्याय, डॉ. रवि प्रकाश आर्य प्रमुख हैं।

उनका कहना है कि यह देखने को मिल रहा है कि इंटरनेट पर सनातन से जुड़ी कई जानकारियां भ्रामक या तोड़-मोड़ कर प्रस्तुत की जा रहीं हैं। जबकि सनातन दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। दो हजार पुस्तकों का निरीक्षण व परीक्षण कर न्यास का यह निष्कर्ष है कि सनातन ही दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। इसके साक्ष्य अलग-अलग देशों में वहां के ग्रंथों में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में सनातन स्वतंत्रता आगे बढ़ी है। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ जैसा आयोजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

उनका कहना है कि सनातन की इस स्वतंत्रता को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए सनातन से जुड़ी सही तथ्यों के प्रचार-प्रसार की जरूरत है। इसके लिए न्यास सनातन आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस लाने की तैयारी में है। इसके लिए शोध चल रहा है और सही तथ्य से अवगत कराने के लिए ग्रंभ भी खंगाले जा रहे हैं। उनके निकले वाले तथ्य इंटरनेट व सनातन एआई से जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति वैश्विक न्यास सिर्फ सनातन अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। इसके आगे सनातन से विश्व की मौजूदा समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है यह बताना है।

सनातन के जरिए पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम भारत की कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य और केन्द्र स्तर पर सांस्कृतिक सलाहकार परिषद जैसी ईकाई का गठन हो जो नीति आयोग की तरह काम करे। इसी तरह सरकार को बौद्धिक संपदा कोष भी बनाना चाहिए।

दीपक सिंघल का मानना है कि मोदी और योगी सरकार ने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में कई काम किए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के अलावा 500 वर्ष बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी सनातन संस्कृति के उदय का प्रतीक है।

शक्ति ने पुलिस परिवार के साथ पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया : डीजीपी

आईएएस में टॉप करने वाली शक्ति दुबे को डीजीपी प्रशांत कुमार ने स्मृति चिन्ह व बुके देकर सम्मानित करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस परिवार के साथ ही पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उल्लेखनीय है कि शक्ति के पिता देवेन्द्र कुमार द्विवेदी कमिश्नरेट, प्रयागराज में उप निरीक्षण के पद पर तैनात हैं।

इस अवसर पर शक्ति दुबे ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे पुलिसकर्मियों के बच्चों को सफलता के टिप्स और उनके सवालों के जवाब भी दिए। परीक्षा यदि एक-दो बार में उत्तीर्ण नहीं कर पाए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहले से अधिक मेहनत व लगन से तैयारी करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज कल हर परीक्षा की तैयारी के लिए लाभप्रद जानकारी सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध है।

शक्ति ने कहा कि परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्व में आए प्रश्न पत्रों को अवश्य हल करें। इससे परीक्षा का पैटर्न पता चलता है। सामाजिक विषयों की जानकारी के लिए रोजाना अखबार पढ़ना जरूरी है। प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के लिए कोई शार्टकट काम नहीं आता है। निरंतर तैयारी के साथ प्रतिदिन लगभग 8 से 10 घंटे की पढ़ाई बेहद जरूरी है। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए हिंदी या अंग्रेजी, किसी भी माध्यम से तैयारी की जा सकती है।

यूपी के चार आईएएस पीएम अवार्ड से सम्मानित

सत्रहवें सिविल सर्वेट दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के जिन आईएएस अफसरों को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया, उनमें चार आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित होने वाले आईएएस अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, भुवनेश कुमार, मोनिका रानी और अनुज सिंह हैं।

अनुराग श्रीवास्तव प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फार एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित हुए। उन्हें जल जीवन मिशन परियोजनाओं में सोलर पावर के अभिनव प्रयोग के लिए यह पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की 80 फीसदी से अधिक परियोजनाएं सोलर पावर पर आधारित हैं। जल जीवन मिशन परियोजना में इतने बड़े पैमाने पर सोलर पावर का इस्तेमाल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 41539 परियोजनाएं हैं। अनुराग श्रीवास्तव 1992 बैच के आईएएस अफसर हैं।

1995 बैच के आईएएस अफसर भुवनेश कुमार को यूआईडीएआई के सीईओ पद पर रहते हुए ई-केवाईसी और फेस अथेंटिकेशन व जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में नई पहल करने के लिए सम्मानित किया गया है। भुवनेश कुमार वर्तमान में केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। यूपी में वह सचिव वित्त के अलावा सचिव एमएसएमई और प्राविधिक शिक्षा विभाग में सचिव के पद पर रहे हैं।

मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह को दिव्यांगों के लिए लाईब्रेरी बनाने और बहराइच के डीएम मोनिका रानी को भी प्रशासनिक कार्यों के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

अनुराग श्रीवास्तव

भुवनेश कुमार

मोनिका रानी

अनुज सिंह

इसलिए दिया जाता है यह पुरस्कार

यह पुरस्कार देशभर के उन चंद चुनिंदा आईएएस अफसरों को दिया जाता है जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए की गई है। इसके तहत कम से कम 5 प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को पुरस्कार के लिए चुना जाता है।

सिविल सेवा परीक्षा–2024

महिलाओं ने किया कमाल 'शक्ति' बन गईं मिसाल

आयुष सिंह

देश की सबसे कड़ी और प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा में इस बार टॉपर बनीं शक्ति दुबे की संघर्ष और सफलता की कहानी को जानने का सबसे सही और उचित तरीका कुछ और नहीं, बस उसकी कविता की पंक्तियों को देख-सुन कर बखूबी समझा जा सकता है। उसकी यह कविता उन्हीं के संघर्षों को बयां करती है। इस कविता का शक्ति के जीवन में कितना गहरा प्रभाव है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी यह कविता इंटरव्यू में भी सुनाई थी।

टॉपर शक्ति की कविता है–

'इमारत को काफी पुरानी है,
इसे गिराकर नई बनाने में वक्त लगेगा।
किस्से तो कई संभाल कर रखे हैं,
उनको कहानी बनाने में वक्त लगेगा।'

अपनी इसी कविता से प्रेरणा लेकर प्रयागराज की बेटी शक्ति दुबे ने सात साल की तैयारी और पांच असफल प्रयासों के बाद यह शानदार मुकाम हासिल कर सबके लिए एक आदर्श और प्रेरणा बन गई है।

शक्ति की सफलता के पीछे की कहानी कुछ यूं है, जिसे बयां कर वह कहती है कि हां हम जानते हैं कि हमारे पीछे कितनी मेहनत लगी थी। मां ने अकेले सब कुछ किया। पिता ने भी हमेशा प्रोत्साहित किया। यहां तक कि यह सपना भी उनका ही था जो मैंने कड़ी मेहनत से पूरा किया।

शक्ति के पिता देवेन्द्र कुमार दुबे ने बताया कि 2023 में उनकी बेटी दो नंबर से चूक गई

25 साल में यूपी ने दिए देश को पांच टॉपर

प्रशासनिक सेवा की देश की सबसे बड़ी इस परीक्षा में लगातार तीन वर्षों से यूपी के मेधावी शीर्ष पर काबिज हैं। संघ लोक सेवा आयोग की इस सिविल सेवा में पिछले 25 परीक्षाओं की बात करें तो यूपी के टॉपरों में बेटियों का ही बोलबाला रहा है।

हैट्रिक लगाने वाले तीन टॉपरों में दो और 25 साल के पांच टॉपरों में तीन बेटियां शामिल हैं, इससे महिलाशक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम 23 मई 2023 को घोषित हुआ था। इसमें ग्रेटर नोएडा की इसिता किशोर ने टॉपर होने का सम्मान पाया था। उस बार टॉप 5 में चार बेटियां शामिल थीं। चौथे स्थान पर प्रयागराज की स्मृति मिश्रा का नाम था। 2023 की सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव को देश में टॉपर होने का गौरव मिला था। उस बार टॉप 5 में यूपी के तीन लड़के थे जबकि दो बेटियों को भी स्थान मिला था।

अब इस बार यानी 2024 की सिविल सेवा परीक्षा में प्रयागराज की बेटी शक्ति दुबे ने पूरे देश में अपने नाम का परचम लहराया है। इस साल टॉप 5 में तीन बेटियों को स्थान मिला है।

725 पुरुष और 284 महिलाओं को मिली सफलता

इस बार कुल 5,83,213 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा दी थी। 14,627 उम्मीदवार लिखित (मेंस) परीक्षा में बैठे थे। इसमें 1,009 सफल हुए थे। इनमें 725 पुरुष और 284 महिलाएं शामिल हैं। कुल 1,129 रिक्तियां भरी जानी हैं। इसमें आईएएस के 180, आईएफएस के 55, आईपीएस के 147, केन्द्रीय ग्रुप-ए सेवाओं में 605 और ग्रुप-बी सेवाओं में 142 पद हैं।

यूपीएससी के अनुसार 241 अनुसंशित उम्मीदवारी अंतिम रखी गई है। जबकि 230 सफल उम्मीदवारों को आरक्षित सूची में रखा है।

सफल उम्मीदवारों में 335 जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से 109, ओबीसी से 318, एससी से 160 और एसटी कैटेगरी से 87 कैंडीडेट्स हैं। टॉप 5 में किसी ने भी साइंस विषय नहीं लिया था।

थी। बायोकेमिस्ट्री में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) से एमएससी करने वाली शक्ति वहां भी गोल्ड मेडलिस्ट रही थी। यह परिवार मूलरुप से देवरिया के बैरिया का रहने वाला है। पुलिस विभाग में कार्यरत शक्ति के पिता और मां प्रेमा दुबे का कहना है कि शक्ति ने बिना किसी कोचिंग के यह कामयाबी हासिल की है।

यूपीएससी में सफलता पाने के मामले में शक्ति का कहना है कि सबसे पहले यूपीएससी के पैटर्न को समझना जरूरी है। एनसीईआरटी की पुस्तकें, सेलेबस और पिछले साल आए प्रश्न पत्रों को साथ लेकर संतुलित तरीके से चलेंगे तो बेहतर तैयारी होगी। अपनी गलतियों से सीखने और उसमें सुधार करने की जरूरत है। असफलता पर यह न सोचें कि सफर पूरा हुआ बल्कि मजबूती से आगे बढ़े। शक्ति इस बार अपनी सफलता के प्रति आशान्वित तो थीं पर उसने यह नहीं सोचा था कि पहली रैंक हासिल कर वह इतिहास रच देगी। तैयारी के बारे में उसने बताया कि आमतौर पर आठ से दस घंटे पढ़ाई करती थी। लेकिन परीक्षा के दौरान कभी-कभी 12 तो कभी 14 घंटे भी लग जाते थे।

दूसरे स्थान पर रहने वाली हर्षिता गोयल हरियाणा के हिसार की मूल निवासी हैं। लेकिन वह बड़ौदा में पली-बढ़ी क्योंकि उसका परिवार वहीं रहता है। शक्ति दुबे की ही तरह दूसरे नंबर पर रहने वाली हर्षिता ने मुख्य परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस एण्ड इंटरनेशनल रिलेशन्स को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था। हर्षिता ने सीए परीक्षा भी पास कर रखी है।

तीसरे स्थान पर रहने वाले वेल्लोर के बीआईटी से बीटेक करने वाले डोंगरे अर्चित पराग ने सिविल सेवा में आने के लिए आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ दी थी और वह पहले ही प्रयास में सफलता की सीढ़ी चढ़ने में कामयाब रहे। अर्चित ने मुख्य परीक्षा में दर्शनशास्त्र को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था।

चौथी रैंक हासिल करने वाली अहमदाबाद गुजरात की मार्गी चिराग को पांचवें प्रयास में सफलता नसीब हुई। मार्गी का कहना है कि मैंने हर बार असफलता से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। कभी भी बोझ नहीं पड़ने दिया। स्वअध्ययन और सटीक मार्ग दर्शन से यह कामयाबी मिली है। मुझे सफलता की उम्मीद तो थी लेकिन टॉप 5 में आउंगी यह नहीं सोचा था। मार्गी चिराग ने मेंस में वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र लिया था।

पांचवे रैंक पाने वाले दिल्ली के आकाश गर्ग ने गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में बीटेक किया है। आकाश को यह उल्लेखनीय सफलता दूसरे प्रयास में

मिली है। उनका वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र था।

मयंक ने पाया दसवां स्थान

कन्नौज के सरायमीरा डाक बंगला रोड निवासी मयंक त्रिपाठी ने दसवां स्थान हासिल कर जिले को गौरवान्वित किया है। पिछली बार मयंक ने 373वीं रैंक हासिल की थी। उसके बाद से वह नागपुर में आईआरएस की ट्रेनिंग में हैं। साल 2022 में मयंक ने पहले प्रयास में पीसीएस की परीक्षा पास कर ली थी।

ऊंची उड़ान भरने वाले UP के अन्य मेधावी

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा-2024 में उत्तर प्रदेश के लिए जहां सर्वाधिक गौरव का विषय टॉपर शक्ति दुबे और कन्नौज के मयंक की दसवीं रैंक है, वहीं यूपी के अन्य अभ्यर्थियों ने भी सिविल सेवा में चयनित होकर अपनी मेधा का परिचय दिया है।

शीर्ष 50 में गोंडा की मुस्कान श्रीवास्तव ने 36वीं रैंक हासिल कर अपनी जिले का नाम रोशन किया है। इसके अलावा जगदीशपुर निवासी किसान के पुत्र अंकुर त्रिपाठी ने 50वीं रैंक हासिल की है। मुस्कान और अंकुर दोनों का चयन पहले आईपीएस में हो चुका था।

लखनऊ का सिर कुमुद मिश्रा और प्रशांत सिंह ने अपनी उपलब्धियों से ऊंचा किया है। कुमुद मिश्रा ने 69वीं रैंक जबकि प्रशांत सिंह ने 102वीं रैंक हासिल की है।

लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली कुमुद मिश्रा ने अपने दूसरे ही प्रयास में आईएएस बनने में सफल रही हैं। पहले प्रयास में कुमुद ने 259वीं रैंक हासिल कर भारतीय राजस्व सेवा में चयनित होने का अवसर पाया था। पर इससे वह संतुष्ट नहीं थीं। अतः उन्होंने उक्त नौकरी ज्वाइन कर अवैतनिक अवकाश लेते हुए पुनः परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी।

कुमुद के अनुसार उन्होंने कोविड काल में घर में बैठे रहने के दौरान यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। कुमुद का कहना है कि परीक्षा में सफलता के लिए सबसे जरूरी है कांसिस्टेंसी डेडीकेशंस। हंड्रेड परसेंट से ही सफलता मिलती है।

102वीं रैंक हासिल करने वाले प्रशांत सिंह का मूलमंत्र है कि असफलता से हार न मानने वाले ही सफलता की मंजिल पर पहुंचते हैं। यही वजह है कि उन्होंने तीन बार असफल रहने के बावजूद हार नहीं मानी और डटे रहे। चौथे प्रयास में भी उतनी ही ऊर्जा से प्रतिदिन आठ घंटे मेहनत की और अंततः सफलता हासिल कर ली। उनकी स्कूली शिक्षा सीएमएस अलीगंज से हुई थी। जबकि स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है।

पैर गंवाने के बावजूद हौसले से भरी उड़ान

वैसे तो लखनऊ के साउथ सिटी निवासी कौशिक मिश्रा को 535वीं रैंक हासिल हुई है। लेकिन सबसे बड़ी और उल्लेखनीय बात यह है कि बारहवीं में एनडीए की परीक्षा के दौरान बायां पैर खोने के बाद सफलता हासिल कर उन्होंने एक मिशाल कायम की है। क्योंकि जब उन्होंने हादसे में अपना बायां पैर खो दिया था तो उन्हें लोगों के तानों के झेलने के दौर से गुजरना पड़ा था। उन्होंने 2018 से यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी।

उन्नाव की बहनें एक साथ बनीं आईएएस

उन्नाव के असोहा क्षेत्र के अजयपुर गांव की रहने वाली दो सगी बहनें सौम्या मिश्रा और सुमेधा मिश्रा (बायें) ने यूपीएससी परीक्षा में अपनी मेधा का लोहा मनवाया।

मिर्जापुर जिले के मड़िहान में बतौर एसडीएम कार्यरत सौम्या की आल इंडिया 18वीं रैंक आई है। वहीं छोटी बहन सुमेधा की आल इंडिया 253वीं रैंक आई है। सौम्या का यह दूसरा अटेम्प्ट था। वहीं सौम्या से तीन साल छोटी बहन सुमेधा का भी यह दूसरा प्रयास था। इनके पिता राघवेन्द्र मिश्रा दिल्ली के एक कालेज में प्रोफेसर हैं। जबकि मां रेणु मिश्रा हाउसवाईफ हैं।

आलू उत्पादन में यूपी अग्रणी

यूपी देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 38 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश में ही पैदा होता है। इस बार भी आलू उत्पादन ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि 6.98 लाख हेक्टेयर में पूरे प्रदेश में आलू की बुआई हुई थी। जबकि उत्पादन 244.65 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है। इससे पहले पिछले साल की बात करें तो तब 6.96 लाख हेक्टेयर में आलू बोया गया था। जबकि उत्पादन का आंकड़ा 243.61 लाख टन था।

किसानों को मिल रहा है सही दाम

सबसे अच्छी बात यह है कि रिकार्ड पैदावार के बावजूद किसानों को सही दाम मिल रहा है। आंकड़ों पर नजर डाले तो प्रदेश में आलू का उत्पादन कई साल से बढ़ रहा है लेकिन एक समय ऐसा था जब पैदावार बढ़ने पर किसानों का संकट बढ़ जाता था। उनको सही दाम नहीं मिलते थे। दो साल पहले तो नौबत यहां तक आ गई थी कि किसानों के लिए लागत निकालना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। इस समय किसानों को सीजन पर भी 700 से 1000 रुपये प्रति कुंटल दाम मिल रहे हैं। वहीं थोक मंडी में यह दाम 1200 से 1600 रुपये प्रति कुंटल है। फुटकर में प्रति किलो 20 रुपये के हिसाब से आलू उपलब्ध है। इस तरह बाजार में संतुलन नजर आ रहा है।

दरअसल सरकार लगातार सबके हितों का ध्यान रखने का प्रयास कर रही है। सरकार की नजर किसानों की समस्याओं को सुलझाने के साथ ही कोल्ड स्टोर और बाजार पर भी नजर है। किसानों को सही दाम मिले और उपभोक्ता की जेब भी न कटे यह ध्यान रखा जा रहा है।

सुधार की वजह

देखा जाए तो आलू किसानों को राहत मिलने की सबसे बड़ी वजह है कोल्ड स्टोरो की संख्या बढ़ना। दो साल पहले (2022-23) तक कोल्ड स्टोरों की कुल भंडारण क्षमता 162.25 लाख मीट्रिक टन ही थी। जबकि उत्पादन 242.93 लाख मीट्रिक टन था। इस तरह दोनों के बीच एक बड़ा अंतर था। अब हालत यह है कि 2024-25 में भंडारण क्षमता बढ़कर 191.64 लाख मीट्रिक टन हो गई है।

उत्पादन बढ़ा है लेकिन उत्पादन और भंडारण क्षमता के बीच अंतर काफी कम हुआ है। इस साल आलू किसानों को एक फायदा यह भी है कि कोल्ड स्टोर मालिकों ने भंडारण दरें भी नहीं बढ़ाई। वहीं दूसरे राज्यों में यूपी का आलू पहुंचे इसके लिए भी सरकार ने बायर-सेलर मीट जैसे आयोजनों के जरिए प्रचार-प्रसार किया है।

आगरा में स्थापित होगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र

सरकार की योजना हाई क्वालिटी के आलू उत्पादन की है। उसके लिए सरकार आगरा में पेरू के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र स्थापित करने जा रही है। इसके लिए हाल ही में प्रदेश और केन्द्र सरकार के बीच एमओयू हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र, पेरू दुनियाभर में आलू पर शोध करने वाला महत्वपूर्ण संस्थान है। अभी इसकी दुनिया में तीन शाखाएं हैं। पेरू, केन्या और चीन के बाद आगरा में यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र होगा। इसके लिए हाल ही में केन्द्र के वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस केन्द्र के लिए आगरा के शौगना आलू प्रक्षेत्र में केन्द्र के लिए दस हेक्टेयर जमीन लीज पर दी जा चुकी है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। आगरा में स्थापित होने वाले इस केन्द्र में अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार होंगे। यहां दूसरे देशों से भी आलू का जर्म प्लाज्म लाकर उससे बीज तैयार किए जाएंगे।

प्रदेश में इस तरह के केन्द्र की बड़ी जरूरत है। क्योंकि जिस रफ्तार से उत्पादन बढ़ रहा है उसको देखते हुए बीज की उपलब्धता बड़ी समस्या है। केन्द्र के स्थापित हो जाने से यह सबसे बड़ा फायदा होगा कि किसानों को खुद बीज तैयार करने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ❑

खुशहाल होता भारत

कौन कितना खुश है इसकी जिज्ञासा आदिमकाल से है। शायद इसी को ध्यान में रखकर और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही लोगों को हर साल वर्ल्ड हैपीनेस रिपोर्ट का इंतजार रहता है।

इस साल की जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है, उसमें खुशी की होड़ में शामिल किए गए दुनिया के 147 देशों में भारत का सीन 118वां है। यद्यपि यह रिपोर्ट उत्साह से कोसों दूर है लेकिन भारत में लोग 2023 के मुकाबले 2024 में ज्यादा खुश रहे। 2023 में भारत की रैंकिंग जहां 126वीं थी तो वहीं हैपीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 147 देशों की सूची में आठ पायदान उपर उठकर 118वें स्थान पर आ गया है। इससे भी बेहतर भारत का पैमाना एक बार 2011 में देखने में आया था। जब भारत के लोगों की खुशहाली का पैमाना 94वें स्थान पर पहुंच गया था। वहीं भारत का सबसे खराब स्कोर 2019 में था जब हैपीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 144वें स्थान पर जगह मिली थी।

खुशहाली की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल लोग फिनलैंड के हैं।

भारत के अन्य पड़ोसियों में श्रीलंका 133वें, बांग्लादेश 134वें और चीन 68वें स्थान पर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट

भारत की किस साल कितनी रही रैंकिंग

वर्ष		रैंकिंग
2024	-	118
2023	-	126
2022	-	126
2021	-	136
2020	-	139

में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा खुश देश बताया गया है। पाकिस्तान इस सूची में 109वें स्थान पर है। यह बहस तलब है कि पाकिस्तान में ज्यादा भ्रष्टाचार, गरीबी, मंहगाई, हिंसा और आतंकवाद है? क्या खुशी की रिपोर्ट तैयार करने वालों के पैमाने में ही दोष है?

इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी छोटे देश के लिए खुश होना ज्यादा आसान है। जबकि एक बड़े देश के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं। चीन खुशहाल और उभरती महाशक्ति का दावा करता है। लेकिन वह दुनिया के 50 सबसे ज्यादा खुश देशों में शामिल नहीं है। भारत तो दुनिया में ऐसी किसी होड़ में शामिल नहीं होता है। पर चीन बढ़ चढ़कर तमाम प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता है। फिर भी वह खुशहाली के पैमाने पर पीछे ही है। कहीं न कहीं चीन की विशाल आबादी भी इसके पीछे आड़े आ रही होगी। चीन बड़ी आबादी के बावजूद भारत से पांच गुना बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत आबादी के लिहाज से अब दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। भारत की विविधता के अलावा उसके तंत्र की उदारता भी कहीं न कहीं खुशी में बाधा बन रही है।

भारत में खुश लोगों की संख्या भी बहुत है और साथ ही दुःखी लोग भी कम नहीं। यहां यह ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि खुशी केवल आर्थिक तरक्की की वजह से नहीं आएगी। देश में आर्थिक व सामाजिक स्तर पर और तेज विकास की जरूरत है। हालांकि बहुत आर्थिक और सामाजिक विकास के बावजूद अमेरिका खिसकते हुए 24वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं फिनलैंड एक बार फिर दुनिया का सबसे खुशहाल देश बनकर उभरा है। उसके बाद डेनमार्क और आईसलैंड का स्थान है।

हेल्थ मंच

गर्मियों में सेहत का साथी

चना और जौ का सत्तू

गर्मियों में लोगों का स्वास्थ की समस्याओं से दो-चार होना ही पड़ता है। इसके चलते लोग गर्मियों में हेल्दी और हल्के भोजन की तलाश में रहते हैं। वहीं गर्मी के मौसम में लोग हैवी, ज्यादा तला-भुना या फिर जंक फूड से परहेज करते हैं क्योंकि यह सभी चीजें पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण बनती हैं। इसी नाते ज्यादातर लोग गर्मी से बचाव और हेल्दी रहने के लिए स्वस्थ और पेय पदार्थों का सेवन करना पसंद करते हैं। जिसमें सत्तू सर्वाधिक चर्चित है।

कई राज्यों मसलन यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में लोग गर्मी से बचाव के लिए जौ या चने का सत्तू पीते हैं। गर्मी के दिनों में सत्तू पीने से शरीर को जहां ठंडक मिलती है वहीं एनर्जी भी भरपूर प्राप्त होती है। केवल यही नहीं कई अन्य स्वास्थ्य फायदे भी मिलते हैं।

सत्तू में कई ऐसे तत्व होते हैं जो डायबिटीज और मोटापे जैसी गंभीर बीमारियों को ही नहीं बल्कि कई दूसरी बीमारियों को भी शरीर से दूर करते हैं। सत्तू खाने में स्वादिष्ट ही नहीं होता बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। सत्तू के औषधीय गुण भी बहुत हैं। जब चना और जौ को साथ में मिलाते हैं तो गर्मियों में यह मिश्रण दवा की तरह काम करता है। चना और जौ को पीसकर सत्तू बनता है। खास बात यह है कि इसका शर्बत, भरवा पराठे या रोटी, पंजीरी, लड्डू, मठरी आदि के रूप में सेवन किया जा सकता है।

मोटापे का दुश्मन

सत्तू एक पूरा आहार है। जिसमें प्रोटीन के साथ मिनरल, आयरन, मैगनीशियम और फास्फोरस बहुत होता है। साथ ही यह फाइबर से भरा होता है। इसे खाने से पेट आसानी से भर जाता है और प्यास भी लगती है।

पानी पीने से पेट देर तक भरा रहता है। ऐसे में यह वजन कम करने के लिए यह बेहतर खाना है।

लू से बचाये

सत्तू की तासीर ठंडी होती है। इस लिए इसे गर्मी में खाने से शरीर ठंडा भी रहता है। और पानी ज्यादा पीने से यह डिहाईड्रेशन से भी बचाता है। इससे लू नहीं लगती है।

एनीमिया में फायदेमंद

सत्तू कैल्सियम, आयरन और प्रोटीन से भी भरा होता है। ऐसे में जिन्हें एनीमिया है वे लोग सत्तू का सेवन जरूर करें।

डायबिटीज में बढ़िया

सत्तू में मौजूद बीटा ग्लूकोन शरीर में बढ़ते ग्लूकोज के अवशोषण को कम करता है। इससे ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है। सत्तू कम ग्लाईसेमिक इंडेक्स वाला होता है। जो डायबिटीज को काबू रखने में मदद करता है।

जौ का सत्तू या चने का सत्तू दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद और पौष्टिक हैं।

अगर आपको पेट से जुड़ी समस्या, डायबिटीज, मलत्याग में समस्या, हाई ब्लडप्रेशर और बार बार भूख लगने की समस्या है तो आप जौ के सत्तू का सेवन आपके लिए लाभकारी है। वहीं अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, वजन कम करना है, इम्यूनिटी मजबूत करनी है या हड्डियां मजबूत करनी हैं तो चने के सत्तू का सेवन लाभप्रद रहेगा। ❑

हिटमैन ने टेस्ट से किया किनारा

पर वनडे में करते रहेंगे धमाल

● वीरेन्द्र शुक्ल
9936403929

कुछ समय से चल रहे कयासों पर आखिरकार हिटमैन रोहित शर्मा ने यह कहकर विराम लगा दिया कि वह अब टेस्ट क्रिकेट में अपनी भूमिका से दूर रहेंगे। इसके साथ ही 280 नंबर की कैप अब भारतीय टेस्ट क्रिकेट में मैदान में अब कभी नजर नहीं आएंगी।

कप्तान ने पद क्या दबाव में तो नहीं छोड़ा

दरअसल 38 वर्षीय रोहित पर न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज और आस्ट्रेलियाई दौरे पर बल्ले से असफलता के बाद टेस्ट से संन्यास का दबाव था। इसी के तहत यह लगने लगा था कि रोहित ने चैंपियंस ट्राफी में देश को गर्वीली जीत दिलाने के बाद ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया था।

निश्चित रूप से टेस्ट में उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। पिछले आठ टेस्ट मैचों में उन्होंने मात्र 164 रन से 10.93 के औसत से ही बनाए थे। इसमें मात्र एक अर्द्धशतक ही शामिल था। जबकि अपने पहले टेस्ट में रोहित ने 177 रनों की शानदार पारी खेलते हुए सबको अपना मुरीद बना लिया था।

हाल के समय में टेस्ट क्रिकेट में रोहित का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहने से उनके नेतृत्व क्षमात पर सवाल उठने लगे थे। उधर चयनकर्ता 2025-27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र को ध्यान में रखते हुए एक दीर्घकालिक कप्तान तैयार करना चाहते थे। ऐसे में यह माना और समझा जा रहा है कि रोहित पर टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहने का नैतिक दबाव भी था।

संन्यास की घोषणा रोहित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टेस्ट कैप की तस्वीर के साथ संदेश पोस्ट कर संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। सफेद कपड़ों में देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव की बात है। इतने वर्षों तक मुझे प्यार करने और मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं देश के लिए वनडे में खेलता रहूंगा।

उल्लेखनीय है कि आस्ट्रेलियाई दौरे पर अंतिम टेस्ट में रोहित ने खराब फार्म के चलते

कौन बनेगा कप्तान ?

अब इंग्लैंड दौरे से पहले चयनकर्ताओं को नए कप्तान की घोषणा करनी होगी।

पांच टेस्टों के इस दौरे की शुरुआत 20 जून से लीड्स में होगी। बुमराह फिलहाल उपकप्तान हैं। उन्हें भी कप्तान बनाया जा सकता है। लेकिन युवा बल्लेबाज शुभमान गिल, लोकेश राहुल और ऋषभ पंत भी दौड़ में हैं।

वैसे कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदारों में से शुभमान गिल सबसे आगे हैं। गिल ने आईपीएल में गुजरात टाईटंस के लिए शानदार कप्तानी की है। वहीं बुमराह के वर्कलोड मैनेमेंट को ध्यान में रखते हुए उनका दावा मजबूत नहीं लगता है। हालांकि दावेदारी को खारिज नहीं किया जा सकता है। उक्त नामों के अलावा ऋषभ पंत भी एक दावेदार के रूप में सामने हैं।

अपने को अंतिम एकादश से अलग कर लिया था। पर उन्होंने उस समय संन्यास लेने से पूरी तरह इंकार कर दिया था। यही नहीं मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ उनके मतभेदों की भी काफी चर्चा रही थी। इसी के साथ पिछले साल जुलाई में कार्यभार संभालने के बाद भारतीय क्रिकेट में स्टार संस्कृति खत्म करने की बात की थी।

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा से पहले रोहित ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप टी-20 से भी संन्यास ले लिया था। जबकि रोहित की कप्तानी में भारत ने पिछले साल टी-20 विश्वकप जीता था। उसी के बाद उन्होंने टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। जबकि उन्होंने क्रिकेट सबसे छोटे प्रारूप में शीर्ष स्कोरर बनकर अलविदा कहा था।

वहीं बीसीसीआई ने भी इस धाकड़ खिलाड़ी के सम्मान में कहा कि - 'धन्यवाद कप्तान, सफेद कपड़ों में यह एक युग का अंत है। रोहित ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। आप वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम की अगुवाई करते रहेंगे। हमें आप पर गर्व है हिटमैन।'

रोहित शर्मा ने यह फैसला इंगलैंड दौरे पर जाने से पहले और आईपीएल के बीच में टेस्ट टीम के नियमित कप्तान से संन्यास की घोषणा कर दी है। टी-20 और टेस्ट से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा ने अपने को पूरी तरह वनडे पर केंद्रित कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि वह 2027 का वर्ल्डकप खेलना चाहते हैं और इस मेगा इवेंट के लिए अपने को फिट रखने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं।

कोवेन्ट्री बनीं आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के 131 वर्षों के लंबे इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी महिला को दुनिया की सर्वोच्च खेल संस्था का अध्यक्ष होने का सम्मान मिला है।

जिंबाब्वे की खेलमंत्री क्रिस्टी कोवेन्ट्री न केवल आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष ही बनी हैं बल्कि किसी अफ्रीकी देश से यह पद पाने वाली वह पहली शख्स भी हैं। कोवेन्ट्री भले ही अब प्रशासनिक पद पर आसीन हुई हैं लेकिन उससे पहले उनका बड़ा ही शानदार खेल इतिहास रहा है। तैराकी में उन्होंने दो बार ओलंपिक चैंपियन बनकर अपने को चर्चित किया था।

कोवेन्ट्री आगामी 23 जून को अध्यक्ष का पद संभालेंगी। इस ओलंपिक दिवस पर वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाख इस पद से कार्यमुक्त हो जाएंगे। 41 वर्षीया कोवेन्ट्री अगले आठ सालों यानी 2033 तक आईओसी की अध्यक्ष बनी रहेंगी।

उन्हें यह पद आसानी या सर्वसम्मति से नहीं मिला है। बल्कि इसके लिए उन्हें वोटिंग का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन उन्होंने वोटिंग के पहले ही दौर में जीत हासिल कर अन्य को पीछे छोड़ दिया। उनकी विजय में थॉमस बाख का भी बड़ा हाथ माना जाता है। क्योंकि उन्हें थॉमस का पूरी तरह समर्थन था। अपनी इस गौरवमयी जीत के दौरान उन्होंने चार अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों के अध्यक्षों को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया। कारण यह कि आईओसी के इतिहास में यह सबसे कड़ा चुनाव था। जिसमें 97 सदस्यों ने हिस्सा लिया था।

अब ओलंपिक में भी लगेंगे चौके और छक्के

अंततः दुनिया के सबसे बड़े खेलमंच पर 128 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद क्रिकेट की वापसी हो ही गई। अब 2028 में लॉस एजेल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में दर्शक चौके-छक्के देखने का लुप्फ उठा सकेंगे।

ओलंपिक में अंतिम बार 1900 में पेरिस में क्रिकेट का आयोजन हुआ था। तब केवल दो ही टीमों फ्रांस और ब्रिटेन ने ही हिस्सा लिया था। हिस्सा लेने वाली 12 टीमों में 6 टीमें पुरुष वर्ग में और इतनी ही महिलावर्ग में शिरकत करेंगी। टी-20 के तर्ज पर होने वाले इन मुकाबलों में कुल 12 देशों की टीमों को खेलने का अवसर मिलेगा।

आँखिन देखी

दरकता दाम्पत्य

वीरेन्द्र सिंह
9410704385

पति-पत्नी का संबंध गंगाजल की तरह पवित्र होता है। एक दूसरे के सम्पूरक होते हैं। परिवार का भरण-पोषण करती है, इसलिए भार्या है। पति के साथ धर्म का निर्वहन करने के कारण पत्नी सहधर्मिणी है परिवार के उदर भरण की वजह से अन्नपूर्णा है। घर-परिवार की लक्ष्मी है। पति की सहचरी है, तो जीवन साथी भी है। गोस्वामी जी लिखते हैं-धीरज, धर्म, मित्र अरू नारी। आपतकाल परखिहंउ चारि।। अर्थात धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। इतना ही नहीं पुरुष की प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं- जिय बिनु देह नदी बिनु वारि, तैसेहि नाथ पुरुष बिनु नारी।। जिस तरह से शरीर बिना प्राण के और नदी बिना पानी के होती है वैसे ही नारी बिना पुरुष के होती है।

इधर नैतिक मूल्यों के निरंतर अवमूल्यन से पति-पत्नी के रिश्तों में खटास आई है। रिश्ते रिसने लगे हैं। परस्पर प्रेम दरकने लगे हैं। बीते दिनों में तो पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या करने की कई सनसनीखेज घटनाएं सामने आई हैं। मेरठ की एक हैरान करने वाली घटना ने पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की न सिर्फ हत्या कर दी बल्कि हत्या के बाद उसके शव के 15 टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की। कर्नाटक के कोडाकू जिले में एक चाय बागान में 54 वर्षीय व्यवसायी रमेश का शव मिला। पुलिस को पता चला कि उसकी पत्नी निहारिका ने प्रेमी निखिल और एक अन्य आरोपी अंकुर ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के रीवां जिले में एक पत्नी ने अपने पति की गला दबाकर हत्याकर दी। पत्नी का किसी दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक महिला ने रेलवे में काम करने वाले पति की हत्या कर दी और गुमराह करने के लिए पुलिस को बताया कि हार्टअटैक से मौत हो गई। पुलिस की जांच में पता चला कि वह रेलवे की नौकरी हथियाने के चक्कर में अपने पति को मार डाला। बलिया जिले में देवेन्द्र कुमार को उसके पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। औरैया जिले में नवविवाहिता ने शादी के महज 14 दिन बाद अपने पति की हत्या कर दी। प्रगति नाम की महिला ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर पति दिलीप की हत्या करके मुंह दिखाई के पैसों और जेवरात लेकर फरार हो गई। हाल ही में बलिया में एक विवाहिता ने अपने रिटायर्ड पति का कत्ल कर दिया। एक युवक से इश्क के चक्कर में पति के कई टुकड़े करके अलग-अलग दिशा में फेंक दिया। ये चंद घटनाएं साबित करती हैं पत्नियों द्वारा पतियों को प्रताड़ित करने की घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन पतियों के संरक्षण के लिए कोई कारगर कानून नहीं है।

क्यों बिखर रहा दाम्पत्य जीवन का ताना बाना। धर्म शास्त्रों से विमुख होना, फूहड़ वेब सीरीज, गंदे मीम, अश्लील यूट्यूब वीडियो, सामजिक नियंत्रण का बिखराव, जरूरत से ज्यादा आजाद खयाली आदि कारण हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में एक चौंकाने वाला तथ्य याचिका के माध्यम से दायर किया गया। महेश कुमार तिवारी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग की है। एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से घरेलू झगड़ों में 81063 पतियों ने आत्महत्या कर ली। याचिका में दावा किया गया है कि देशभर में 164033 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से आत्महत्या करने वाले विवाहित पुरुषों की संख्या 81063 थी जबकि 28680 शादी शुदा महिलाएं थीं।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि विकसित देशों जैसे यूके, अमेरिका, कनाड़ा में घरेलू हिंसा का कानून जेंडर न्यूट्रल है, जबकि इंडिया में स्पेसिफिक है। यानी सिर्फ महिलाओं के लिए है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो इस इश्यू को डील कर सके। याचिका में पुरुषों को भी महिलाओं की भांति समान अधिकार देने की बात कही गई है।

सुखमय और शांतिमय पारिवारिक जीवन के लिए यह जरूरी है कि पति-पत्नी के रिश्ते बेहतर बने रहें। आपसी संवाद बनाए रखें। एक-दूसरे को समय दें। एक-दूसरे के प्रति विश्वास में कमी न आने दें। एक-दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझने की कोशिश करें। एक साथ मिलकर लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। जब गलती हो तो माफी मांगने और देने से रिश्ता मजबूत होता है। एक-दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें। ❑

27 टका टंच, मीडिया मंच

पीयूष त्रिपाठी
7518839758

अपने प्रिय पात्र चचा चकल्लस के चेहरे पर चमक और चुलबुलापन देखकर उन्हे रोका फिर टोका कि क्या बात है। चचा आज तो एकदम मस्त लग रहे हैं क्या हुआ। चचा बोले-जिसके यहां 27 साला पत्रिका जवान हो चुकी हो और थिरक-थिरक कर नाच भी जाने आंगन भी सीधा कर दे तो मस्ती आएगी ही। तुम क्या जानो बकलोल पत्रकारिता के कीचड़ में लिथड़े प्राणी हो-आगे नाथ न पीछे पगहा वाले बैल सरीखे दूसरे अखबारों के उगाए खेतों की हरियाली चरने वाले प्राणी ये देख 27 साला सुधर-सलोनी जवान पत्रिका। चचा ने मीडिया मंच पत्रिका मुझे थमा दी और बोले घूर कर न देखना। जोर से न पढ़ना, पढ़कर फेंकना नहीं, वरना तेरी मनहूस नजर लग जाएगी समझे कुछ। मैंने कहा चचा मीडिया मंच शुरु करने में मैं भी था- मेरी नजर क्यों लगेगी ?

चचा भड़क उठे- जिसकी नजर चढ़ती जवानी पर लफंडरों की नजरें गड़ी जिसको उछलते, कूदते, थिरकते, पनपते देख जाने कितनों की छाती पर एनाकोंडा लोट रहे हों। जिसकी मौजूदगी से ही टीबी हो रही हो। अरे हां टीबी से याद आया तेजबहादुर सिंह नाम। अमेठी से लखनऊ आकर टीबी सिंह हो गया। अच्छे भले नाम का सत्यानाश कर दिया- वहां क्या भरोसा कि तुम मीडिया मंच का नाम टीबिया टंच न कर डालो वैसे सौ टका टंच हो जाने के बाद मंच तो मंच है। कोई क्या कर लेगा। चचा कंटीन्यू चालू थे। मैने कहां चुप्प अब जो बोले तो यही मीडियामंच मुंह पर मारूंगा। चचा एक मिनट चुप रहे फिर बोले-बेटवा मैं तो मजाक कर रहा था, जब मीडिया मजाक बन कर रह गया हो, जब मीडिया की औकात टके-टके की रह जा रही हो तो थोड़ा सा मजाक मैं भी कर सकता हूं। वैसे सच कहूं तो 27 साल तक एक मैंग्जीन को पालना-पोसना, उसकी चमक बनाए रखना, सिस्टम बनाए रखना, उसको जालसाजों, लफ्फाजों, कारसाजों से बचाए रखना, चलाए रखना मुझे तो एवरेस्ट पर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल लगता है। स्क्रीन पर चमकती इंटरनेट पर कुलांचे मारती पत्रकारिता की पुंगी बजाती सोशल मीडिया पर ता थैया नाचती मीडिया, धन्नासेठों की गुफाओं से निकलती, पूंजीपतियों की तिजोरियों में मचलती मीडिया के बाजार में किताब की शक्ल धारण किए कोई पत्रिका 27 साल तक बनी रहे यही बहुत बड़ी कामयाबी है, उपलब्धि है। मेहनत की मूरत और सक्रियता की सूरत है।

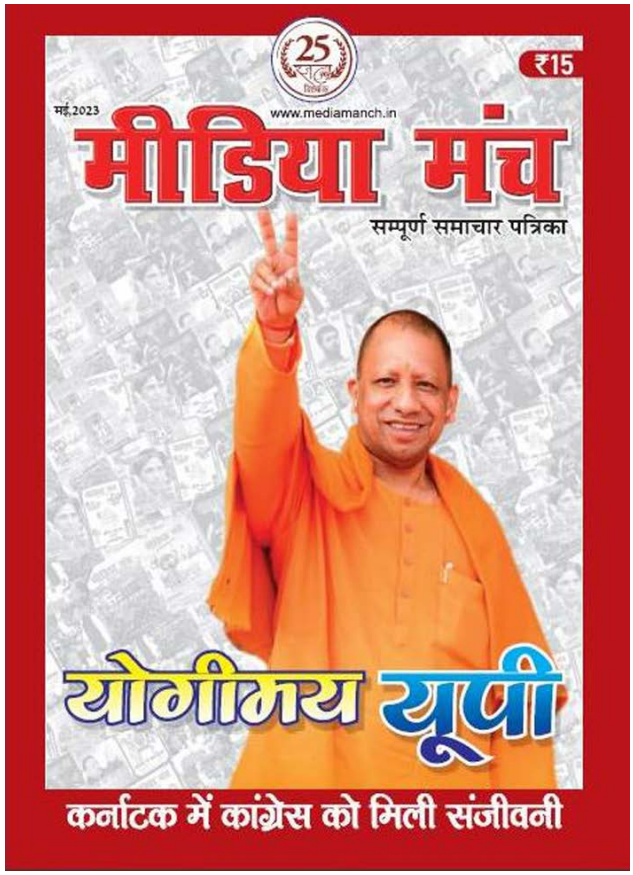

बोलो क्या कहते हो ? चचा कुछ सीरियस दिखे तो मैंने कहा -अरे चचा आप तो सीरियस हो गए। चकल्लसी आदमी सीरियस हो तो वैसा ही दिखता है जैसे दूसरे के मंच पर मीडिया इसलिए आप सीरियस न हों चकल्लस फैलाते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, त्रस्त तो आप पहले से हैं। रही बात मीडिया मंच की तो भाई गजब है यह टीबी सिंह नाम का प्राणी और शुरूआत से मीडिया मंच को पकड़कर लटक गए कई अन्य प्राणी जो जबसे मीडिया मंच पकड़े छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। लोग सात जन्मों का साथ निभाते हैं ये 27 जन्मों तक का ठेका लेकर बैठे हैं। कौन-कौन हैं ? तो मीडिया मंच में उनके नाम पढ़ लीजिएगा- इतने लग्घड़ हैं कि पिंड नहीं छोड़ रहे। इनको सबको शुक्रिया ही नहीं शुक्रिया का बाप। मुबारकबाद का टाप। मीडिया मंच की जवानी तक का साथ देने में यूपी की ब्यूरोक्रेसी का भी बड़ा हाथ और पांव दोनों हैं। ताली बजाकर उत्साह बढ़ाते हैं, सहयोग करते हैं। कुछ पालिटिशयन भी खीसें निकालकर बैकअप कर देते हैं। कई विज्ञापन दाता झोली खोलकर देते हैं। एडीटोरियल टीम भी काम के दाम पर जिद नहीं करती।

इसलिए न ऋण की चिंता न धन की चोट- ये टीबी सिंह काहे मोट। यही वजह है कि मीडिया मंच झक्कास जवान हो गयी। और एक मंच बनकर मचल रही है। तो चचा आप कुछ समझे कि नहीं- इतना कहते ही चचा भड़क उठे- अच्छा तो नासमझ कहा मुझे- जा तेरा वाट्सप एकाउंट बंद हो जाए, इंस्टा सस्पेंड हो जाए, तेरी रील करप्ट हो जाय। सरकार तेरी निगरानी बढ़ा दे। तू डिजिटल अरेस्ट हो जाए साइबर ठगों को तेरे पास से कुछ न मिले। सूचना विभाग तेरे विज्ञापन बंद कर दे। बाबा का घंटा तेरे सिर पर बजे अरे-अरे ये डिजीटली बद्दुआयें बंद कीजिए चचा। 27 साला जश्न मनाइए। तब कहीं चचा शांत हुए और बोले 27 लड्डू चाहिए। वरना नौ का पहाड़ा सुना। जय हो मीडिया मंच।

प्रखर पत्रकार राव का निधन

शिव शंकर गोस्वामी

इंडियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (आईएफडब्ल्यूजे) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड कोटामराजू विक्रम राव का 12 मई को लखनऊ में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। उनके निधन से पूरे देश के पत्रकारों में शोक की लहर व्याप्त हो गयी। वह कि विक्रम राव पिछले 41 साल से आईएफडब्ल्यूजे के एकछत्र अध्यक्ष रहे हैं। संगठन भले ही दो फाड़ हो गया हो किन्तु विक्रम राव जब एक बार आईएफडब्ल्यूजे के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे तो ताजिन्दगी उस पर विराजमान रहे। सच बताने की आवश्यकता नहीं है कि विक्रम राव सही मायने में एक प्रतिबद्ध पत्रकार थे।

हिन्दी, अंग्रेजी, तेलगू तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं पर उनका पूरा कमांड था। इसका एक कारण यह भी था कि पत्राकारिता उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता के. रामाराव नेशनल हेराल्ड के सम्पादक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। के. विक्रम राव ने अपनी पत्रकारिता टाइम्स आफ इंडिया के अहमदाबाद संस्करण से शुरू की थी और बाद में कुछ अन्य बडे अखबारों में भी उनके योगदान के उदाहरण मिलते हैं। मरने के तीन दिन पहले तक भी सोशल मीडिया एवं कुछ राष्ट्रीय दैनिक में उन का लेख प्रकाशित हुआ। यह इस बात का गवाह है कि वै कितने सक्रिय पत्रकार थे। मीडिया की दुनिया में उनके चाहने वालों की संख्या बहुत थी। बताने की आवश्यकता नहीं कि आईएफडब्ल्यूजे दुनिया भर में पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन है और विक्रम राव 41 सालों से इसके एक छत्र अध्यक्ष रहे हैं।

1984 में फैजाबाद अब अयोध्या में आयोजित फेडरेशन के महाअधिवेशन में राव साहब को अध्यक्ष चुना गया था। तब उन्होंने ए. राघवन से कार्यभार संभाला था। जनमोर्चा के तत्कालीन सम्पादक शीतला सिंह उस अधिवेशन के संयोजक थे। कामरेड संतोष कुमार को फेडरेशन का महासचिव चुना गया था। वर्ष 1984 के अधिवेशन के बाद राव साहब का कद ज्वालामुखी की तरह बढता गया और अपनी सदारत में उन्होंने देश के हर महानगरों में पत्रकारों के बड़े-बड़े सम्मेलन करवाए। इसमें से मुम्बई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, बंगलोर, गोवा, चेन्नई, त्रिवैन्दरम, कन्याकुमारी, अहमदाबाद, कुरुक्षेत्र, शिमला, गोरखपुर, बहराइच, माउंट आबू, चण्डीगढ, झांसी, भोपाल, पुरी, जैसलमेर, जयपुर यहाँ तक कि लखनऊ और इलाहाबाद व प्रयागराज जैसे शानदार आयोजन कराया।

आईएफडब्ल्यूजे का आंदोलन आज भले ही बिखर गया हो किन्तु इससे विक्रम राव की महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता हैं। उनकी लड़ाई की बदौलत अस्सी के दशक में पालेकर आयोग बनी जिसने पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के वेतनमान तथा उनकी सेवा शर्तों की सिफारीशें की। यह बात अलग है कि सरकार की ढिलाई के चलते मालिकों ने उस सिफारिश को लागू नहीं किया। विक्रम राव चुप नहीं बैठें। लड़ झगड कर उन्होंने बछावत एवं मेहसाणा वेतन बोर्डों का गठन कराया लेकिन उसका भी हश्र पालेकर वेतन बोर्ड वाला ही हुआ। आज पत्रकारों की न तो कोई सेवा शर्त रह गयीं हैं और ना ही कोई वेतनमान। लगभग ज्यादातर पत्रकार संविदा पर अल्प वेतनमान में काम करने को मजबूर हैं। ना पेंशन की सूविधा न ग्रेच्युटी एवं फंड की सुविधा। सरकार भी चुप है। वह भी इस चौथे स्तम्भ का मजाक ही उड़ाती है। विक्रम राव तो रहे नहीं। पत्रकारों की आवाज कौन उठायेगा और कौन सुनेगा। विक्रम राव कितने जुझारू थे इसका एक ही उदाहरण काफी है। 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ तब विक्रम राव को तत्कालीन सोशलिस्ट नेता जार्ज फर्नांडीज के साथ डायनामाइट केस बडौदा की जेल में 20 महीने से अधिक समय तक बन्द रखा गया लेकिन उनकी लेखनी की धार कभी कम नहीं हुई।

श्रमिक आंदोलनों में भाग लेने वाले किसी भी पत्रकार को कोई अखबार मालिक अपने यहाँ रखना नहीं चाहता। इसलिये नौकरी जाने की डर से अब पत्रकार लोग श्रमिक आंदोलनों से मुह मोड़ चुकें है। और जब पत्रकार ही नहीं रहेंगे तो आईएफबीडीओ का अस्तित्व कहाँ रहेगा। अच्छी बुरी बातें हर एक मंच पर कहने को होती हैं लेकिन कामरेड विक्रम राव के योगदान को पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ❑

वरिष्ठ पत्रकार के. विक्रम राव को एनेक्सी मीडिया सेंटर में दी गई श्रद्धाजलि

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति ने देश के प्रख्यात पत्रकार एवं इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (आईएफडब्ल्यूजे) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. के. विक्रम राव के निधन पर शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा में वरिष्ठ पत्रकारों ने श्री राव के निधन को पत्रकारिता के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। समिति के सचिव भारत सिंह ने वरिष्ठ पत्रकारों से अपनी स्मृति साझा करने का अनुरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि डा. राव पत्रकारिता के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय थे और उन्होंने श्रमजीवी पत्रकारों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया।

उनका जीवन संघर्षशील पत्रकारिता, सिद्धांतनिष्ठ विचारों और निर्भीक लेखनी का पर्याय रहा, उनके निधन से पत्रकारिता जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। शोकसभा में वरिष्ठ पत्रकार समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी, विजय शंकर पंकज, राकेश पाण्डेय, प्रद्युमन तिवारी, राजीव वाजपेई, प्रेमकांत तिवारी, डा. कलानिधि मिश्रा, भास्कर दुबे, सीके शर्मा, मनमोहन, टीवी सिंह, देवकी नंदन मिश्रा, सिद्धार्थ कलहंस ने अपनी स्मृति साझा किया।

किंग खान अब भी सिर्फ 5 घंटे सोते हैं

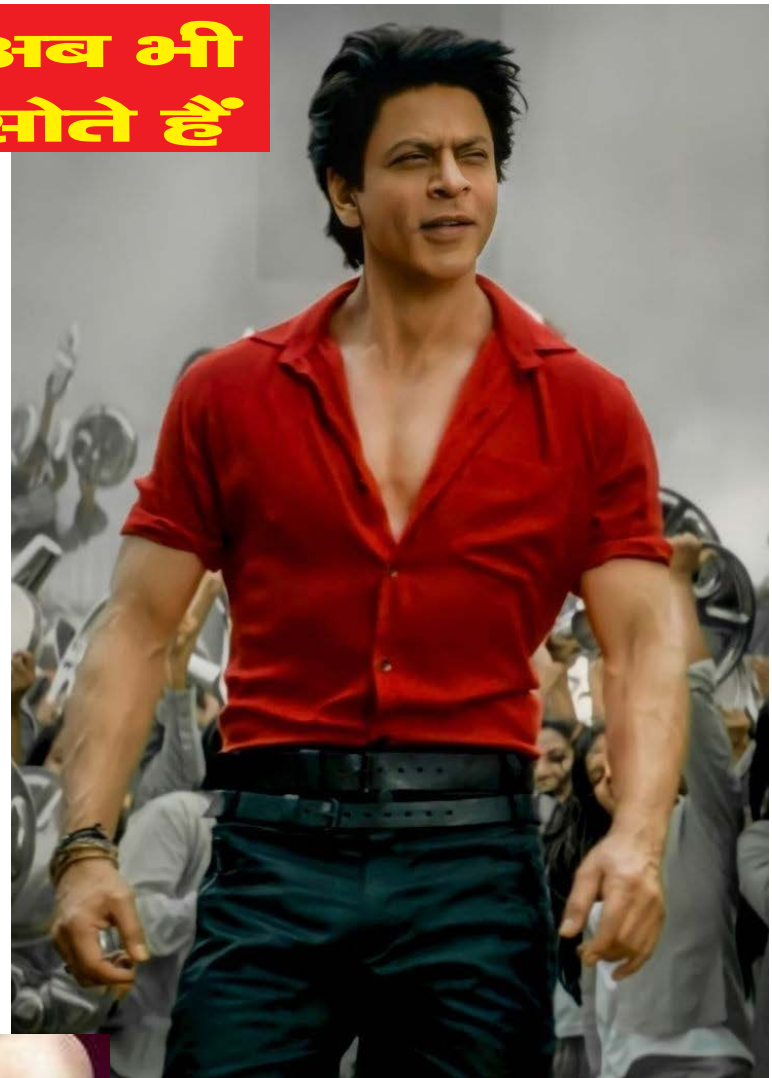

बढ़ती उम्र के बावजूद किंग खान अब भी काफी काम को लेकर सक्रिय और सचेत हैं। वह 59 साल के हो चुके हैं लेकिन वह अब भी सुबह पांच बजे तक काम में लगे रहते हैं। नतीजा यह है कि वह सोने के लिए मात्र पांच घंटे ही निकाल पाते हैं। बावजूद इसके वह चुस्ती-फुर्ती में कहीं से भी कम नजर नहीं आते हैं। इस उम्र में भी वह इतने चुस्त-दुरूस्त और तंदरूस्त नजर आते हैं कि लोग उनसे उनकी सेहत का राज पूछने लगते हैं।

दरअसल शाहरूख खान की व्यस्तता इस कारण बढ़ी हुई है कि वे अपने बेटे आर्यन खान और बेटी सुहानी को अभिनय की दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। इन दिनों वह बेटे आर्यन की वेबसीरीज 'बैड्स आफ बालीवुड' और बेटी सुहानी की बड़े पर्दे के लिए बन रही फिल्म 'किंग' को फाइनल टच देने में लग हुए हैं।

अपने शुभचिंतकों और सेहत का राज जानने वाले लोगों को वह बताते हैं कि मेरे काम करने और भोजन का तरीका दोनों ही बीते तमाम वर्षों में बदला नहीं है। मैं सुबह पांच बजे तक काम करता हूं। खाने में अंकुरित बीज, ब्रोकली, थोड़ी सी दाल और भुना हुआ चिकन वर्षों से मेरी पहली पसंद है। मेरे खाने में तब्दीली तभी होती है जब घर में कोई मेहमान आता है। तब मैं खुद को नहीं रोकता।

कोरोना संक्रमण काल में जब सब बंद था तो मैंने सबसे कोई नया हुनर सीखने की इच्छा के तहत खुद को जिम के हवाले कर दिया। मेरा सुगठित शरीर उसी समय की कि गई कसरतों की देन है।

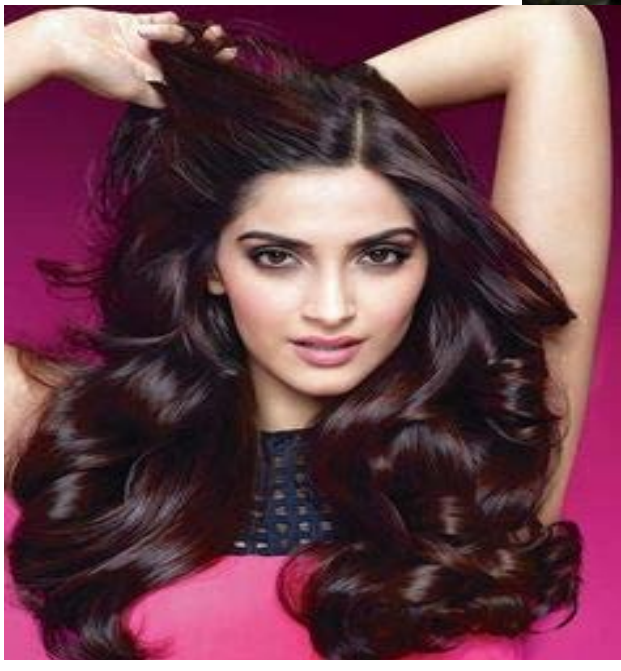

फैशन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं : सोनम

अभिनेत्री सोनम कपूर को बालीवुड में अपने बेहतरीन फैशन सेंस के लिए जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने फैशन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

सोनम ने कहा कि बीते सालों में भारत ने ग्लोबल फैशन मैप पर अपनी जगह बनाई है। मै भारत की विविधता, गहराई और क्षमता को सामने लाना चाहती हूं। और यह भी चाहती हूं कि ग्लोबल ब्रांड्स हमारे समृद्ध, सांस्कृतिक मूल्यों के सम्मन के लिए काम करूं।

दरअसल फैशन मेरे लिए सिर्फ खूबसूरती से जुड़ा नहीं है बल्कि यह कहानी कहने और अपनी पहचान से भी जुड़ा है। मेरा मानना है कि फैशन किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाता है। यह तो खुद को जाहिर करने का तरीका है। यह हमारी पर्सनैलिटी का विस्तारित रूप होता है। मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्टाईल और ट्रेंड के मुताबिक तैयार होना पड़ता है। लेकिन मैं अंततः अपनी सांस्कृतिक विरासत लिए भारतीय डिजाईन पर वापस लौटती हूं। ❑

जाति जनगणनाः बिहार से तय होगी दिशा

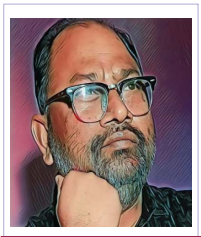

हेमंत तिवारी
मो.-9889433333

केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना कराने का एलान कर विपक्ष को उसके ही हथियार से मारने का दांव चल दिया है या वो विपक्ष के बनाए चक्रव्यूह में फंस गए हैं ये तो समय बताएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक (पीडीए) की राजनीति को धार देने में जुटा है और भाजपा ने आगे बढ़कर जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया है उससे साफ लगता है कि डेढ़ साल बाद होने वाला यूपी का विधानसभा चुनाव पिछड़ों की जमीन पर लड़ा जाएगा।

जाति जनगणना को लेकर भाजपा में उहापोह की स्थिति रही है और ये हालात अभी भी नजर आती है। जाति गणना के सवाल पर भाजपा के अगड़ी पांत के अगड़े नेता बहुत उत्साह में नहीं दिखते हैं वहीं भाजपा में पिछड़ों के चैंपियन केशव प्रसाद मौर्य इस मुद्दे पर खुलकर विपक्ष पर हमलावर हैं। मौर्य इस मुद्दे पर पूरी सक्रियता के साथ सामने आए हैं। उनका रुख स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि भाजपा के भीतर ओबीसी नेतृत्व अब खुलकर सामाजिक न्याय की मांगों को समर्थन दे रहा है। उनका कांशीराम को उद्धृत करना भाजपा की रणनीति में एक बहुजन एंगल को जोड़ने की कोशिश है।

वहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की राजनीति हिंदू एकता पर आधारित रही है, जो जातीय पहचान को गौण मानती है। वे जातीय जनगणना को हिंदू समाज को बांटने की एक साजिश मानते रहे हैं, खासकर विपक्ष द्वारा मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के इरादे से। इसलिए जब केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की, तो यह उनके पूर्ववर्ती बयानों से टकराव में आ गया। नतीजतन, वह केवल एक औपचारिक ट्वीट तक सीमित रहे, जो उनकी राजनीतिक असहजता को दर्शाता है।

हालांकि हाल के दिनों में अपने संबोधनों में जरूर योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को भाजपा के लिए गेम चेंजर मानते हुए विपक्ष द्वारा पिछड़ों की अनदेखी और जाति विशेष को ही तरजीह दिए जाने के लेकर हमला बोल रहे हैं।

> जाति जनगणना के एलान के बाद राजनीति बदली है या वहीं खड़ी है, इसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट बिहार में होगा, जहां इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे। तेवरों से लगता है कि इसका क्रेडिट लेते हुए भाजपा व उसके सहयोगी बिहार में चुनाव मैदान में उतरेंगे और सफल होने की दशा में कुछ ही महीनों बाद होने वाले यूपी के चुनाव में वहीं राह पकड़ेंगे।

दरअसल पारंपरिक रूप से जातीय पहचान की राजनीति से दूरी बनाकर रखने वाली भाजपा अब इस जाति जनगणना को डेटा आधारित सुशासन के नाम पर अपना रही है। उसका मानना है कि जाति जनगणना एक डेटा आधारित प्रक्रिया है जिसके सामने आने पर भारतीय राजनीति बदल जाएगी। इससे साफ है कि सामाजिक न्याय की राजनीति जो अब तक सपा-बसपा-कांग्रेस जैसी पार्टियों के हिस्से का इलाका माना जाता है, वह भाजपा के एजेंडे में आ चुका है। भले ही प्रस्तुतीकरण अलग हो और नाम व नारा अलग, पर भाजपा ये मान चुकी है कि आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति बदलने जा रही है जहां पिछडे केंद्र में होंगे।

जाति जनगणना का एलान और उसके बाद का घटनाक्रम भाजपा में एक पार्टी के तौर पर चल रहे वैचारिक संघर्ष को भी दिखाता है और जबकि यह साफ है कि इस साल होने वाले बिहार के चुनाव में और बाद में होने वाले अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। विपक्ष भी इसे खूब समझ रहा है। बिहार में राहुल गांधी की यात्राएं व जिन जातीय समूहों से वे मिल रहे हैं, सब यही संकेत देते हैं।

इतना साफ दिख रहा है कि अब सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और हिंदू एकता की परिभाषाएं दोबारा लिखी जा रही हैं और राजनैतिक पार्टियां इन जातियों को संबोधित करने को मजबूर हैं, जिन्हें अब तक वो महज वोट बैंक मानती थीं।

यहां यूपी के मुखिया व भाजपा के अब अगड़ी पांत के सबसे प्रमुख नेताओं में शुमार हो चुके योगी आदित्यनाथ के कंधे पर दोहरा भार है। उन्हें संघ की हिन्दू एकता की मशाल का वाहक भी बनना है और सामाजिक न्याय की राजनीति को भी साथ लेकर चलना है। अब तक के संकेत तो बताते हैं कि योगी अपनी मेहनत से विपरीत ध्रुवों को भी साध सकते हैं। ❑

hemant.jansandesh@gmail.com

उत्तर प्रदेश नं. 1

- देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में प्रथम
- 56 लाख+ परिवारों के लिए पक्के आवास
- पीएम किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में प्रथम
- 1.86 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन का वितरण
- स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि ऋण वितरण में प्रथम
- सर्वाधिक 2.75 करोड़ शौचालयों का निर्माण
- 15 करोड़ नागरिकों को नि:शुल्क राशन का वितरण
- 60 लाख माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना सहायता
- 1.58 करोड़ घरों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन
- 9 करोड़+ लोगों को ₹5 लाख तक का नि:शुल्क उपचार
- 9.57 करोड़ लोगों का जन धन बैंक खाता
- 1 करोड़ परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरित

Published on10th & Posted on 15th, 17th & 19th of every month at RMS Lucknow. Total number of pages 52.
RNI No. UPHIN/1998/5628

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

उपलब्धियां

पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य 3930 किमी0 के सापेक्ष 2795.84 किमी0 का कार्य 2703.84 करोड की लागत से पूर्ण किया जा चुका है।

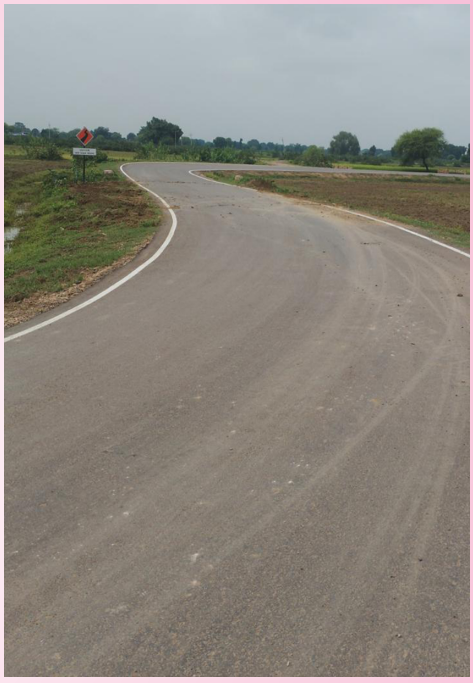

☛ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने वाले प्रोत्साहन धनराशि के अंतर्गत यूपीआरआरडीए ने सीजीबीएम, एमएमएस+, वेस्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स आदि नई प्रौद्योगिकियों के साथ पीरियाडिक रिन्यूवल कार्यों के लिए 494.02 करोड़ रुपये की लागत से लबाई 1911.30 किमी, 306 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

☛ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत नई तकनीक एफ0डी0आर0 के अन्तर्गत निर्मित मार्गों की मॉनिटरिंग हेतु उत्तम पोर्टल को विकसित किया गया है। उत्तम पोर्टल के परफार्मेन्स के मूल्यांकन के पश्चात् ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तम पोर्टल को सम्पूर्ण भारत में पैन इण्डिया बेसिस पर लागू किये जाने हेतु अग्रसर है जो कि एक बड़ी उपलब्धि है।

☛ पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नई तकनीक एफ0डी0आर0 में अग्रणी रहा है तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में 19 राज्यों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण / हैण्ड होल्डिंग भी किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में नई तकनीक एफ0डी0आर0 में 5400.00 किमी0 मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके कारण 1045.82 करोड़ की धनराशि की बचत किये जाने के साथ-साथ 85.65 लाख घनमी0 (5.35 लाख ट्रक लोड) नई पत्थर की गिट्टी एवं 650 लाख घनमी0 डीजल की बचत करते हुए पर्यावरण को संरक्षित किया जा रहा है, जो स्वयं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

☛ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई-4 की शुरुआत की गयी है, जिसकी गाईडलाइन के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आकांक्षात्मक जनपदों और आकांक्षात्मक ब्लॉक में 250+ आबादी एवं शेष अन्य क्षेत्रों में 500+ आबादी की अनजुड़े बसावटों सर्वऋतु सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना है। ग्राम सड़क सर्वेक्षण एप्लिकेशन का उपयोग करते हुये अनजुड़ी बसावटों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 14800 बस्तियाँ सम्मिलित हैं।

☛ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएमजीएसवाई-3 (वित्तीय वर्ष 2024-25, बैच 1) के 03 सड़क, लम्बाई 21.9 किलोमीटर एवं 60 मीटर की 01 एलएसबी/सेतु की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

☛ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए विकसित भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) डाटा सार्वजनिक डोमेन जारी किया है। उत्तर प्रदेश ने पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण मार्ग, बसावटें, कोर नेटवर्क, चिकित्सा, शैक्षिक एवं अन्य जनसुविधाओं को जिओ टैग कर समस्त विवरण सार्वजनिक डोमेन में https;//geosadak-pmgsy.nic.in/opendata पर उपलब्ध है।